



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 72]

नई दिल्ली, बुधवार, अप्रैल 6, 2011/चैत्र 16, 1933

No. 72]

NEW DELHI, WEDNESDAY, APRIL 6, 2011/CHAITRA 16, 1933

देना बैंक

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 अक्टूबर, 2010

फा. सं. आई आर/696/2010.—बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम 1970 (1970 का 5) की धारा 12 की उप-धारा (2) के साथ पठित धारा 19 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, देना बैंक का निदेशक मंडल, भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श से और केन्द्रीय सरकार की पूर्व मंजूरी से, एतद्वारा देना बैंक (अधिकारी) सेवा विनियम, 1979 में आगे संशोधन करने हेतु निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् :—

1. (1) ये विनियम देना बैंक (अधिकारी) सेवा (संशोधन) विनियम, 2010 कहलायेंगे।
- (2) ये विनियम जहां कहीं अन्यथा उल्लेख किया गया हो, उसे छोड़ कर 2 जून, 2005 से लागू होंगे।
2. देना बैंक (अधिकारी) सेवा विनियम, 1979 (इसके बाद कथित विनियमों के रूप में संदर्भित) में विनियम 3 में —
  - (i) खंड (जी) के लिए निम्नलिखित खंड प्रतिस्थापित होगा, अर्थात्—
 

(जी) “परिवार” अर्थात् अधिकारी का पति/की पत्नी (जो बैंक का/की कर्मचारी नहीं है) पूर्णतः आश्रित अविवाहित बच्चे (सौतेले बच्चे तथा विधिक रूप से गोद लिए हुए बच्चों सहित) एवं माता-पिता जो सामान्यतया अधिकारी के साथ रहते हों एवं पूर्णतः आश्रित हों,
  - (ii) खंड (ओ) के लिए निम्नलिखित खंड प्रतिस्थापित होगा, अर्थात्—
 

(ओ) “पूर्णतः आश्रित बच्चे या माता-पिता” का अर्थ है बच्चे या माता-पिता जिनकी आय रुपये 2550 प्रतिमास से अधिक न हो।

**टिप्पणी :** यदि माता-पिता में से एक की आय रुपये 2550 प्रति मास से अधिक है या माता-पिता दोनों की कुल आय रुपये 2550 से अधिक है, तो माता-पिता दोनों ही अधिकारी पर आश्रित नहीं समझे जाएंगे।

3. कथित विनियमों में विनियम 4 में उप-विनियम (4) के लिए निम्नलिखित विनियम प्रतिस्थापित होगा, अर्थात्:-

'(4) नवंबर 2002 के प्रथम दिन और तब से प्रत्येक श्रेणी के सामने उल्लिखित वेतनमान निम्नलिखित अनुसार होगा-

ए) उच्च कार्यपालक श्रेणी :

$$\text{वेतनमान VII} = \text{रु. } 29340 - \frac{680}{2} - 30700 - \frac{900}{1} - 31600 - \frac{1000}{1} - 32600$$

$$\text{वेतनमान VI} = \text{रु. } 26620 - \frac{680}{4} - 29340$$

बी) वरिष्ठ प्रबंधन श्रेणी

$$\text{वेतनमान V} = \text{रु. } 24140 - \frac{620}{4} - 26620$$

$$\text{वेतनमान IV} = \text{रु. } 20480 - \frac{560}{1} - 21040 - \frac{620}{5} - 24140$$

सी) मध्य प्रबंधन श्रेणी

$$\text{वेतनमान III} = \text{रु. } 18240 - \frac{560}{5} - 21040 - \frac{620}{2} - 22280$$

$$\text{वेतनमान II} = \text{रु. } 13820 - \frac{500}{1} - 14320 - \frac{560}{10} - 19920$$

डी) कनिष्ठ प्रबंधन श्रेणी :

$$\text{वेतनमान I} = \text{रु. } 10000 - \frac{470}{6} - 12820 - \frac{500}{3} - 14320 - \frac{560}{7} - 18240$$

टिप्पणी:

31 अक्टूबर, 2002 को लागू वेतनमानों द्वारा शासित होने वाले प्रत्येक अधिकारी का नियतन 1 नवंबर, 2002 को इस उप-विनियम में निर्धारित वेतनमान में प्रक्रम-दर-प्रक्रम आधार पर किया जाएगा, अर्थात् पहले प्रक्रम से तदनुरूपी प्रक्रमों पर और वेतनवृद्धियां, अन्यथा उपबंधित को छोड़कर, सामान्यतया अधिवर्षिता तारीख को देय होंगी.

(4 ए) उप-विनियम (1), (2) (3) एवं (4) की किसी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जाए कि बैंक के लिए हर समय इन सभी श्रेणियों में अधिकारी रखना अपेक्षित है।

4. उक्त विनियमों में, विनियम 5 के लिए, निम्नलिखित विनियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात:-

'5 वेतनवृद्धियां: (1) विनियम 4 के उप विनियम (4) के उपबंधों के अधीन 1 नवंबर, 2002 को और उस तारीख से, वेतनवृद्धियां निम्नलिखित शर्तों के अधीन मंजूर की जाएगी, अर्थात:-

- (ए) विनियम 4 के उपविनियम (4) में उपवर्णित वेतनमानों में विनिर्दिष्ट वेतनवृद्धियां, सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी के अध्यक्षीन वार्षिक आधार पर प्रोद्भूत होगी और जिम महीने में देय होती हो, उस महीने की पहली तारीख को दी जाएगी.
- (बी) वेतनमान I तथा वेतनमान II के अधिकारियों को, अपने संबंधित वेतनमानों के अधिकतम पर पहुंचने के एक वर्ष पश्चात, अगले उच्च वेतनमान में अवरोध वेतनवृद्धि (यां) सहित आगे की वेतनवृद्धियां केवल नीचे (ग) में विनिर्दिष्ट आधार पर दी जाएगी, बशर्ते कि वे सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार दक्षतारोध को पार कर लें.
- (सी) ऊपर (बी) में उल्लिखित अधिकारियों सहित, मध्य प्रबंधन श्रेणी वेतनमान II तथा III के अधिकतम पर पहुंचने के पश्चात् प्रत्येक 3 वर्षों की सेवा पूरी होने पर अवरोध वेतनवृद्धि (यां) दी जाएगी/जाएगी. वेतनमान II के अंतिम प्रक्रम पर पहुंच चुके अधिकारियों के मामले में रुपये 560/- की अधिक से अधिक दो वेतनवृद्धियां दी जाएगी तथा वेतनमान III के अंतिम प्रक्रम के अधिकारियों के मामले में रु.620/- की एक वेतनवृद्धि दी जाएगी. परंतु 1 नवंबर 1994 को या उसके बाद से मूल वेतनमान III में अधिकारियों को अर्थात् जो वेतनमान III में भर्ती या पदोन्नत हुए हैं, दूसरी अवरोध वेतनवृद्धि पहली अवरोध वेतनवृद्धि पाने के तीन वर्ष बाद प्रदान की जाएगी. परंतु अगले उच्च वेतनमान में ऐसी वेतनवृद्धि/यां अवरोध वेतनवृद्धि/यां उस अधिकारी को नहीं दी जाएगी जो प्रस्ताव किए जाने पर पदोन्नति हेतु इंकार करता है.

टिप्पणी: अगले उच्चतर वेतनमान में की गई ऐसी वेतनवृद्धियों को पदोन्नति नहीं माना जाएगा. ऐसी वेतनवृद्धियां पाने के पश्चात भी अधिकारी को, यथा स्थिति, उसके अपने मूल पद के वेतनमान I अथवा II के ही विशेषाधिकार, परिलब्धियां, ड्यूटी, उत्तरदायित्व अथवा पद मिलेंगे.

- (2) सीएआईबी का भाग I/ भारतीय बैंकर संस्थान की जूनियर एसोसिएट तथा सर्टिफाइड एसोसिएट ऑफ इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ बैंकर्स भाग II /भारतीय बैंकर संस्थान की प्रमाणपत्रित एसोसिएट परीक्षा उत्तीर्ण करने पर वेतनमान में एक अतिरिक्त वेतनवृद्धि प्रदान की जाएगी.

स्पष्टीकरण : (ए) जिस अधिकारी ने नियत तारीख से पहले अधिकारी के रूप में भारतीय बैंकर संस्थान की प्रमाणपत्रित एसोसिएट (सर्टिफाइड एसोसिएट ऑफ इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ बैंकर्स ) परीक्षा का भाग I अथवा भाग II उत्तीर्ण कर ली हो, उसे नियत तिथि से, यथास्थिति, अतिरिक्त वेतनवृद्धि अथवा वेतनवृद्धियां दी जाएंगी, बशर्ते कि उसने उक्त परीक्षा के दोनों भाग उत्तीर्ण करने पर कोई वेतनवृद्धि न ली हो अथवा केवल एक वेतनवृद्धि ली हो.

- (बी) दि.1.11.1987 को तथा उसके बाद से, वेतनमान के अधिकतम पर पहुंचने वाले अथवा पहुंच चुके ऐसे अधिकारियों को, जो पदोन्नति बिना और आगे नहीं जा सकते, सरकारी दिशानिर्देशों के अधीन, यदि कोई हों, सर्टिफाइड एसोसिएट ऑफ इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ बैंकर्स परीक्षा उत्तीर्ण करने के फलस्वरूप अतिरिक्त वेतनवृद्धियों के स्थान पर निम्नानुसार व्यावसायिक अर्हता भत्ता दिया जाएगा:

#### तालिका

जिन्होंने सर्टिफाइड एसोसिएट ऑफ इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ बैंकर्स का केवल भाग-I उत्तीर्ण किया है :	(i) एक वर्ष पश्चात् रु.100/- प्र.मा. जिनमें से रु.75/- अधिवर्षिता लाभ के लिए गिने जाएंगे.
जिन्होंने सर्टिफाइड एसोसिएट ऑफ इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ बैंकर्स के दोनों भाग उत्तीर्ण कर लिए हैं :	(i) एक वर्ष पश्चात् रु.100/-प्रति मा. जिसमें से रु.75/- अधिवर्षिता लाभ के लिए गिने जाएंगे.
	(ii) 2 वर्ष पश्चात् रु.250/- प्रति.मास जिसमें से रु.200/- अधिवर्षिता लाभ के लिए गिने जाएंगे.

- (सी) दिनांक 1 नवम्बर, 1994 को तथा उसके बाद से, अन्य बातें समान होने पर, व्यावसायिक अर्हता भत्ते की मात्रा निम्नानुसार संशोधित रहेंगी :

## तालिका

जिन्होंने सर्टिफाइड एसोशिएट ऑफ इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ बैंकर्स परीक्षा का केवल भाग I उत्तीर्ण किया है	(i) वेतनमान के उच्चतम बिन्दु पर पहुंचने के एक वर्ष बाद रु.120/- प्र.मा.
जिन्होंने सर्टिफाइड एसोशिएट ऑफ इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ बैंकर्स परीक्षा के दोनों भाग उत्तीर्ण कर लिए हैं :	(i) वेतनमान के उच्चतम बिन्दु पर पहुंचने के एक वर्ष बाद रु.120/- प्र.मा.  (ii) वेतनमान के अधिकतम पर पहुंचने के दो वर्ष बाद रु.300/- प्र.मा.

परंतु, विनियम 5के उप-विनियम (3) के खंड (बी) के अनुसार नियत वैयक्तिक भत्ता प्राप्त करने के पात्र अधिकारी, यथास्थिति, क्रमशः भाग I या II के लिए ऐसा नियत वैयक्तिक भत्ता पाने के एक/दो वर्षों के पश्चात् व्यावसायिक अर्हता भत्ता प्राप्त कर सकेंगे.

(डी) दि.1 नवम्बर, 1999 को और उसके बाद से, अन्य बातें समान होने पर, व्यावसायिक अर्हता भत्ते के भुगतान की मात्रा निम्नलिखित तालिका में दर्शाए गए अनुसार पुनरीक्षित होगी:

## तालिका

जिन्होंने जूनियर एसोशिएट ऑफ इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ बैंकर्स अथवा सर्टिफाइड एसोशिएट ऑफ इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ बैंकर्स का भाग-I उत्तीर्ण किया है:	(i) वेतनमान के उच्चतम बिन्दु पर पहुंचने के एक वर्ष बाद रु.150/- प्र.मा.
जिन्होंने जिन्होंने जूनियर एसोशिएट ऑफ इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ बैंकर्स एवं सर्टिफाइड एसोशिएट ऑफ इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ बैंकर्स अथवा सर्टिफाइड एसोशिएट ऑफ इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ बैंकर्स के दोनों भाग उत्तीर्ण कर लिए हैं:	(i) वेतनमान के उच्चतम बिन्दु पर पहुंचने के एक वर्ष बाद रु.150/- प्र.मा. (ii) वेतनमान के अधिकतम पर पहुंचने के दो वर्ष बाद रु.360/- प्र.मा.

परंतु जो अधिकारी वेतनमान I और II में हैं तथा वे उप-विनियम 1 के खंड (बी) के अनुसार अगले उच्चतर वेतनमान में अधिकतम पर पहुंचने के, यथास्थिति, एक/दो वर्ष पश्चात् व्यावसायिक अर्हता भत्ता प्राप्त करेंगे.

(ई) दिनांक 1 नवम्बर 2002 को एवं उसके बाद से अन्य बातें समान होने पर, व्यावसायिक अर्हता भत्ते के भुगतान की मात्रा निम्नलिखित तालिका में दर्शाए गए अनुसार पुनरीक्षित होगी:

## तालिका

जिन्होंने जूनियर एसोशिएट ऑफ इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ बैंकर्स परीक्षा अथवा सर्टिफाइड एसोशिएट ऑफ इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ बैंकर्स परीक्षा का केवल भाग I उत्तीर्ण किया है	(i) वेतनमान के उच्चतम बिन्दु पर पहुंचने के एक वर्ष बाद रु.300/- प्र.मा.
जिन्होंने सर्टिफाइड एसोशिएट ऑफ इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ बैंकर्स परीक्षा के दोनों भाग उत्तीर्ण कर लिए हैं :	(i) वेतनमान के उच्चतम बिन्दु पर पहुंचने के एक वर्ष बाद रु.300/- प्र.मा. (ii) वेतनमान के अधिकतम पर पहुंचने के दो वर्ष बाद रु. 750/- प्र.मा.

परंतु जो अधिकारी वेतनमान I और II में हैं तथा वे उप-विनियम 1 के खंड (बी) के अनुसार अगले उच्चतर वेतनमान में अधिकतम पर पहुंचने के, यथास्थिति, एक/दो वर्ष पश्चात् व्यावसायिक अर्हता भत्ता प्राप्त करेंगे.

टिप्पणी : (i) यदि किसी ऐसे अधिकारी को जिसे व्यावसायिक अर्हता भत्ता मिल रहा हो, उसे अगले उच्चतर वेतनमान में पदोन्नत किया जाता है, तो ऐसे उच्चतर वेतनमान में उसका वेतन निर्धारित करते समय, उसे वेतनमान में उपलब्ध वेतनवृद्धियों की सीमा तक जूनियर एसोशिएट ऑफ इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ बैंकर्स/सर्टिफाइड एसोशिएट ऑफ इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ बैंकर्स की परीक्षा उत्तीर्ण करने पर अतिरिक्त वेतनवृद्धियां दी जाएंगी और यदि वेतनमान में कोई वेतनवृद्धियां उपलब्ध नहीं है, तो अधिकारी वेतनवृद्धि(यों) के एवज में व्यावसायिक अर्हता भत्ता पाने का पात्र होगा.

(ii) दि.1 नवम्बर 1994 को तथा उसके बाद से, यथास्थिति, व्यावसायिक अर्हता भत्ते या व्यावसायिक अर्हता वेतन, जैसे भी स्थिति हो, को महंगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता तथा अधिवर्षिता लाभों के लिए गिना जाएगा.

(iii) अधिकारी व्यावसायिक अर्हता वेतन के पात्र नहीं होगा, यदि वह प्रस्ताव किए जाने पर पदोन्नति के लिए इंकार करता है.

(iv) यदि कोई अधिकारी वेतन के उच्चतम वेतनमान में पहुंचने के बाद जूनियर एसोशिएट ऑफ इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ बैंकर्स या सर्टिफाइड एसोशिएट ऑफ इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ बैंकर्स (एक या दोनों भाग) उत्तीर्ण करता है, तो उसे ऐसी अर्हता प्राप्त करने की तारीख से व्यावसायिक अर्हता वेतन की प्रथम किस्त मंजूर की जाएंगी एवं व्यावसायिक अर्हता भुगतान की बाद की किस्तें प्रथम किस्त जारी किए जाने की तारीख के संदर्भ में विमुक्त की जाएंगी.

(v) यदि कोई अधिकारी, 2 जून 2005 को खंड (iv) में संदर्भित अर्हता प्राप्त कर चुका है एवं उसने ऐसी अर्हता प्राप्त करने पर कोई वेतनवृद्धि या व्यावसायिक अर्हता वेतन अर्जित नहीं किया है, उसे 1 नवंबर, 2002, या ऐसी अर्हता/एं प्राप्त करने की तारीख में से जो भी बाद में हो, से उपरोक्त उपबंधित किए गए अनुसार व्यावसायिक अर्हता वेतन जारी किया जाएगा.

(3) (ए) जो अधिकारी 01 नवम्बर 1993 को बैंक की स्थायी सेवा में है उन्हें वेतनमान में एक अग्रिम वेतनवृद्धि दी जाएगी और जो अधिकारी 01 नवम्बर 1993 को परिवीक्षा पर हैं उन्हें एक अग्रिम वेतनवृद्धि स्थायीकरण के एक वर्ष पश्चात् दी जाएगी.

टिप्पणी : अग्रिम वेतनवृद्धि के कारण वार्षिक वेतनवृद्धि की तारीख में कोई परिवर्तन नहीं होगा.

(बी) जो अधिकारी वेतनमान के अधिकतम पर पहुंच चुका है या जो 01 नवम्बर 1993 को अवरोध वेतनवृद्धि(यां) प्राप्त कर चुका है, वह 01 नवम्बर 1993 से नियत वैयक्तिक भत्ता प्राप्त कर सकेगा, जो 01 नवम्बर 1993 को अंतिम आहरित वेतनवृद्धि तथा उस पर देय महंगाई भत्ता तथा विनियम 22 के अनुसार लागू दरों पर मकान किराया भत्ते की मात्रा के बराबर होगा. यहां नीचे तालिका में दिया गया नियत वैयक्तिक भत्ता तथा साथ ही

साथ मकान किराया भत्ता, यदि कोई हो आगे संशोधित होने तक वैध बना रहेगा.

### तालिका

वेतनवृद्धि घटक	वेतनवृद्धि घटक पर दि. 01.11.1993 को महंगाई भत्ता	जहां बैंक का आवास उपलब्ध कराया गया है वहां देय कुल नियत वैयक्तिक भत्ता
(क)रु.	(ख)रु.	(ग)रु.
230	5.79	236
250	6.30	257
300	7.56	308
400	10.08	411

(सी) दिनांक 1 नवंबर 1999 को या उसके बाद से अन्य चीजों के समान रहते हुए नियत वैयक्तिक वेतन, मकान किराया भत्ता, यदि कोई हो, सहित निम्नानुसार दिया जाएगा

### तालिका

वेतनवृद्धि घटक	वेतनवृद्धि घटक पर दि. 1.11.1997 को महंगाई भत्ता	बैंक द्वारा उपलब्ध आवासीय सुविधा की दशा में कुल देय नियत वैयक्तिक भत्ता
(क)रू.	(ख)रू.	(ग)रू.
340	4.28	345
380	4.78	385
420	5.29	426
600	7.56	608

(डी) दिनांक 1 नवंबर, 2004 का एवं उसके बाद से, अन्य बातें समान होने पर नियत वैयक्तिक वेतन, मकान किराया भत्ता सहित, यदि कोई हो, नीचे तालिका में दर्शाए गए अनुसार होगा और सेवा की पूरी अवधि के लिए अवरुद्ध बना रहेगा.

### तालिका

वेतनवृद्धि घटक	वेतनवृद्धि घटक पर दि. 01.11.2002 को महंगाई भत्ता	बैंक द्वारा उपलब्ध आवासीय सुविधा की दशा में कुल देय नियत वैयक्तिक भत्ता
(क)रू.	(ख)रू.	(ग)रू.
560	23	583
620	25	645
680	28	708
1000	41	1041

टिप्पणी : (i) विनियम 5 के उप-विनियम (3) के खंड (बी), (सी) एवं (डी) में टेबल के कॉलम (सी) में दर्शाये गए के अनुसार नियत वैयक्तिक भत्ता उन अधिकारी कर्मचारियों को दिया जाएगा जिन्हें बैंक द्वारा आवास उपलब्ध कराया गया है.

(ii) मकान किराया भत्ता के पात्र अधिकारियों के लिए नियत वैयक्तिक भत्ता/नियत वैयक्तिक भुगतान विनियम 5 के उप-विनियम (3) के खंड (बी), (सी) एवं (डी) में विनिर्दिष्टानुसार संबंधित वेतनमान की अंतिम वेतनवृद्धि प्राप्त कर लेने पर (ए) + (बी) + संबद्ध अधिकारी कर्मचारियों द्वारा आहरित मकान किराया भत्ता होगा, जैसा कि विनियम (4) के उप-विनियम (2) एवं (3) में दर्शाया गया है.



(iii) दिनांक 1 नवंबर 1999 को या उसके बाद से नियत वैयक्तिक भत्ता जारी करने के बारे में उप विनियम (2) के (सी) में दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार व्यावसायिक अर्हता वेतन जारी करने की अनुसूची में कोई परिवर्तन नहीं होगा।

परंतु, जहां व्यावसायिक अर्हता वेतन की कोई किस्त, जो पूर्व के प्रावधानों के कारण एक वर्ष तक बढ़ा दी गई थी तथा दिनांक 1 नवंबर 1999 को या उसके बाद जारी की जाने वाली है, अधिकारी को इस तिथि को या से दी जाएगी और व्यावसायिक अर्हता वेतन, यदि कोई हो, की दूसरी किस्त 1 नवंबर 2000 को दी जाएगी।

(iv) नियत वैयक्तिक भत्ते/ नियत वैयक्तिक वेतन के वेतनवृद्धि घटक को अधिवर्षिता लाभ के लिए गिना जाएगा।

(ई) जिस अधिकारी को उपर्युक्त (ए) के अनुसार वेतनवृद्धि मिल चुकी है उसे ऊपर (बी), (सी) या (डी) में उल्लिखित नियत वैयक्तिक भत्ते/ नियत वैयक्तिक वेतन की मात्रा, वेतनमान के अधिकतम पर पहुंचने के एक वर्ष पश्चात् प्राप्त होगी।

5. विनियम 21 में उप-विनियम (3) के पश्चात् निम्नलिखित उप-विनियम जोड़ा जाएगा, अर्थात्-

(4) 1 नवंबर, 2002 को तथा उसके बाद से, महंगाई भत्ता योजना इस प्रकार होगी:-

(ए) महंगाई भत्ता अखिल भारतीय औसत श्रमिक वर्ग उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, सामान्य- आधार 1960 = 100 के तिमाही औसत में 2288 अंकों के ऊपर 4 अंकों की प्रत्येक वृद्धि अथवा गिरावट के हिसाब से संदेय होगा।

(बी) 1 नवंबर, 2002 से 31 जनवरी, 2005 तक की अवधि के दौरान महंगाई भत्ता निम्नलिखित दरों पर संदेय होगा :

(i) रु. 9650/- तक 'वेतन' का 0.18% (+)

(ii) रु. 9650/- के अधिक परंतु रु. 15,350/- तक 'वेतन' का 0.15% (+)

(iii) रु. 15350/- से अधिक परंतु रु. 16350/- तक 'वेतन' का 0.09% (+)

(iv) रु. 16350/- से ऊपर 'वेतन' का 0.04%

(सी) 1 फरवरी 2005 को और तबसे महंगाई भत्ता वेतन के 0.18% की दर से देय होगा.

टिप्पणी: (ए) महंगाई भत्ते के प्रयोजन हेतु 'वेतन' से मूल वेतन तथा अवरोध वेतनवृद्धियां अभिप्रेत हैं.

(बी) विनियम 5 के नियम (2) के स्पष्टीकरण (सी) (डी) और (ई) में निर्दिष्टानुसार, व्यावसायिक अर्हता भत्ते/व्यावसायिक अर्हता वेतन को महंगाई भत्तों के लिए गिना जाएगा.

6. इन विनियमों में विनियम 22 के लिए निम्नलिखित विनियम प्रतिस्थापित किया जाएगा अर्थात्:-

'22 मकान किराया भत्ता : (1) (ए) 1 नवम्बर, 1999 को या उसके बाद से, यदि किसी अधिकारी को बैंक द्वारा आवासीय सुविधा प्रदान की जाती है तो उससे वह जिस वेतनमान में है उसके प्रथम प्रक्रम में मूल वेतन के 2.5% के बराबर रकम या आवास हेतु मानक किराया, जो भी कम हो, वसूल किया जाएगा.

(बी) 1 नवम्बर, 1999 को या उसके बाद से, यदि किसी अधिकारी को बैंक द्वारा आवासीय सुविधा प्रदान नहीं की जाती है तो वह निम्नलिखित दरों पर मकान किराया भत्ता पाने का पात्र होगा.

#### तालिका

कार्यस्थल निम्नलिखित स्थानों पर होने पर	देय मकान किराया भत्ता
(1)	(2)
(i) केन्द्र सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार समय-समय पर विनिर्दिष्ट प्रमुख 'ए' वर्ग के शहर एवं समूह 'ए' में परियोजना क्षेत्र केन्द्र	वेतन का 9% प्र.मा.
(ii) क्षेत्र I में अन्य स्थान तथा समूह 'बी' में परियोजना क्षेत्र केन्द्र.	वेतन का 8% प्र.मा.
iii) क्षेत्र II अर्थात् उपर्युक्त (i) और (ii) के अंतर्गत न आने वाले सभी स्थान	वेतन का 7% प्र.मा.

परंतु यदि कोई अधिकारी किराए की रसीद प्रस्तुत करता है तो उसे देय मकान किराया भत्ता, जिस वेतनमान में वह है उसके प्रथम प्रक्रम के 2.5% के ऊपर, उसके द्वारा अपने आवास के लिए दिया गया वास्तविक किराया या ऊपर कॉलम (2) के अनुसार देय मकान किराया भत्ते का 150%, में से जो भी कम हो, होगा.

- (2) (ए) दि.01 नवम्बर, 2002 को और उसके बाद से यदि किसी अधिकारी को बैंक द्वारा आवासीय सुविधा प्रदान की जाती है तो उससे वह जिस वेतनमान में है उससे प्रथम प्रक्रम में मूल वेतन के 1.75% के बराबर रकम या आवास हेतु मानक किराया, जो भी कम हो, वसूल किया जाए.
- (बी) दि. 1 नवम्बर, 2002 को और उसके बाद से, यदि अधिकारी को बैंक द्वारा आवासीय सुविधा प्रदान नहीं की जाती है तो वह निम्नलिखित दरों पर मकान किराया भत्ता पाने का पात्र होगा.

### तालिका

कार्यस्थल निम्नलिखित स्थानों पर होने पर	देय मकान किराया भत्ता
(1)	(2)
(i) प्रमुख 'ए' वर्ग के शहर एवं समूह 'ए' में परियोजना क्षेत्र केन्द्र	वेतन का 8.5% प्र.मा.
(ii) क्षेत्र I में अन्य स्थान तथा समूह 'बी' में परियोजना क्षेत्र केन्द्र.	वेतन का 7.5% प्र.मा.
iii) अन्य स्थान	वेतन का 6.5% प्र.मा.

परंतु यदि कोई अधिकारी किराए की रसीद प्रस्तुत करता है तो उसे देय मकान किराया भत्ता, जिस वेतनमान में वह है उसे प्रथम प्रक्रम के 1.75% से ऊपर, उसके द्वारा अपने आवास के लिए दिया गया वास्तविक किराया, अधिकतम ऊपर तालिका में कॉलम (2) के अनुसार देय मकान किराया भत्ते का 150%,

- (3) यदि कोई अधिकारी अपने ही मकान में रहता है तो वह उप-विनियम (1) का खंड (बी) और उप विनियम (2) के खंड (बी) में उल्लिखित किए गए अनुसार समान आधार पर मकान किराया भत्ते का हकदार होगा, मानो वह नीचे (ए) अथवा '(बी)' में उच्चतर के बारहवें भाग के बराबर मासिक किराया दे रहा हो.

(ए)

निम्नलिखित का योग :-

- (i) निवास स्थान के लिए देय नगर पालिका कर, और
  - (ii) भूमि की लागत सहित निवास स्थान की पूंजीगत लागत का 12% और यदि निवास स्थान किसी भवन का भाग है तो उतने भाग की भूमि के आनुपातिक हिस्से की पूंजीगत लागत, किंतु इसके अंतर्गत वातानुकूल जैसे विशेष जुड़नार शामिल नहीं होंगे, या
- (बी)

निवास स्थान के लिए नगरपालिका कर निर्धारण हेतु आंका गया वार्षिक किराया मूल्य.

स्पष्टीकरण:

(1) इस विनियम के प्रयोजन से “मानक किराया” का अर्थ होगा:-

- (ए) बैंक के स्वामित्व के निवास के मामले में मानक किराये की गणना सरकार में प्रवर्तमान ऐसी गणना की पद्धति के अनुसार की जाएगी.
- (बी) जहां कहीं निवास बैंक द्वारा किराये पर लिये जाते हैं, बैंक द्वारा देय संविदागत किराया या ऊपर (ए) में दर्शाई गई पद्धति के अनुसार गणना किए गए किराये में से जो भी कम हो.

- (2) मकान किराया भत्ते के प्रयोजन हेतु ‘वेतन’ का अर्थ है-अवरोध वेतनवृद्धियां सहित मूल वेतन.
- (3) 1 नवम्बर, 1994 से मकान किराया भत्ते के प्रयोजन हेतु, यथास्थिति, व्यावसायिक अर्हता भत्ता या व्यावसायिक अर्हता भुगतान को गणना में लिया जाएगा.
- (4) इस विनियम और विनियम 23 के उप-विनियम (1) एवं (2) के प्रयोजन हेतु, क्षेत्र I और क्षेत्र II से निम्न अभिप्राय है:-

- क्षेत्र - I - 12 लाख से अधिक जनसंख्या वाले स्थान
- क्षेत्र - II - वे सभी स्थान जो क्षेत्र I में शामिल नहीं किए गए हैं.

7. कथित विनियमों में विनियम 23 के लिए निम्नलिखित विनियम प्रतिस्थापित किया जाएगा:-

'23 अन्य भत्ते :

- (1) 1 नवम्बर, 2002 को और उसके बाद से अधिकारी निम्नलिखित तालिका में दर्शाए गए अनुसार नगर प्रतिकर भत्ता पाने का पात्र होगा.

तालिका

स्थान	दरें
(1)	(2)
(ए) क्षेत्र-I के स्थान और गोवा राज्य में	मूल वेतन का 4. % अधिकतम रु.540/- प्रतिमाह
(बी) पांच लाख या उससे अधिक जनसंख्या वाले स्थान और राज्यों की राजधानियां तथा चंडीगढ़, पोंडिचरी और पोर्ट ब्लेयर जो ऊपर लिखित (ए) में नहीं आते हैं.	मूल वेतन का 3. %, बशर्ते कि अधिकतम रु.375/- प्रतिमाह हो.
(सी) अन्य स्थान	शून्य

- (2) 1 नवंबर, 2002 को और उसके बाद से विशेष एरिया भत्ते की दर इन विनियमों से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट किए गए अनुसार होगी.
- (3) 1 नवंबर, 2002 को या उसके बाद से यदि कोई अधिकारी समूह ए या समूह बी के अंतर्गत आने वाले किसी प्रोजेक्ट क्षेत्र के रूप में विनिर्दिष्ट किसी क्षेत्र में सेवाएं दे रहा है, तो वह समूह ए या समूह बी के रूप में क्षेत्र के वर्गीकरण के अनुसार प्रतिमास रुपये 210/- या रुपये 185/- की दर पर प्रोजेक्ट क्षेत्र प्रतिकर भत्ता पाने का हकदार होगा.
- (4) 1 जनवरी, 2004 को या उसके बाद से यदि किसी अधिकारी का शैक्षणिक वर्ष के मध्य में एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरण होता है और उसे एक या अधिक बच्चे हैं, जो पूर्व के स्थान पर स्कूल या कॉलेज में पढ़ रहे हैं, वह बाद के स्थान पर रिपोर्ट करने की तारीख से सभी अध्ययनरत बच्चों के संबंध में शैक्षणिक वर्ष की समाप्ति तक की अवधि हेतु रुपये 500/- प्रतिमास की दर पर मध्य-शैक्षणिक वर्ष स्थानांतरण भत्ते के लिए हकदार होगा.

परन्तु यदि सभी बच्चे पूर्व के स्थान पर अध्ययन बंद करते हैं तो ऐसा भत्ता बंद कर दिया जायेगा.

- (5) 1 जून 2005 को और उसके बाद से, यदि किसी अधिकारी को बैंक से बाहर सेवा के लिये प्रतिनियुक्त किया जाता है तो वह प्रतिनियुक्ति के पद पर देय उन परिलब्धियों को प्राप्त करने के लिए अपना विकल्प दे सकता है. विकल्पतः वह अपने वेतन के अतिरिक्त वेतन का 7.75%, अधिकतम रु.1500/- प्रतिमाह प्रतिनियुक्ति भत्ता और ऐसे अन्य भत्ते ले सकता है जो उसे उसी स्थान पर बैंक की सेवा में तैनात होने की स्थिति में मिलते.

परन्तु यदि उसे उसकी प्रतिनियुक्ति से पूर्व उसकी तैनाती के स्थान पर ही स्थित किसी संगठन में प्रतिनियुक्त किया जाता है तो उसे उसके वेतन का 4% अधिकतम रु.750/- प्रतिनियुक्ति भत्ता मिलेगा.

परन्तु यह भी कि जिस अधिकारी को बैंक के प्रशिक्षण संस्थान में संकाय सदस्य के रूप में प्रतिनियुक्त किया जाता है उसे उसके वेतन का 4% अधिकतम रु. 750/- प्रतिनियुक्ति भत्ता मिलेगा.

- (6) यदि किसी अधिकारी से कम से कम 7 दिन लगातार या महीने के दौरान कुल सात दिन किसी उच्चतर श्रेणी में किसी पद पर स्थानापन्न रूप से कार्य लिया जाता है तो उसे स्थानापन्न रूप में कार्य करने की अवधि के लिए उसके वेतन का 6% वेतन के अनुसार स्थानापन्न अवधि हेतु आनुपातिक आधार पर स्थानापन्न भत्ता मिलेगा. स्थानापन्न भत्ते को भविष्य निधि एवं पेन्शन के लिए ही हिसाब में लिया जाएगा.

परन्तु यदि कोई अधिकारी विनियम 6 के अधीन पदों के प्रवर्गीकरण के मात्र पुनरीक्षण के परिणामस्वरूप उच्चतर वेतनमान में स्थानापन्न रूप में कार्य करता है तो उसे प्रवर्गीकरण के पुनरीक्षण के प्रभावी होने की तारीख से एक वर्ष की अवधि के लिए स्थानापन्न भत्ता नहीं मिलेगा.

- (7) यदि अधिकारी को किसी शाखा में तैनात किया जाता है जहां बहियां दिनांक 1 अप्रैल एवं 30 सितम्बर को बंद की जाती हैं, वह दो लेखाबंदी हेतु रुपये 250/- प्रत्येक की दर पर लेखाबंदी भत्ता पाने का हकदार होगा.

- (8) दिनांक 1 नवंबर, 2002 को एवं उसके बाद से किसी अधिकारी के कामकाज के घंटे दिन में न्यूनतम दो घंटे के अंतराल पर बंद बांट दिए जाते हैं, वहां वह अधिकारी रुपये 125/- प्रतिमाह की दर पर स्प्लीट ड्यूटी भत्ता पाने का हकदार होगा।
- (9) यदि किसी अधिकारी को छुट्टी के किसी दिन वॉल्ट या लॉकर के अभिरक्षक के रूप में कार्य करना होता है तो वह उस पर देय दैनिक भत्ता पाने का हकदार होगा, जिसके लिए वह पात्र है।
- (10) 1 नवम्बर, 2002 को और उसके बाद से, अधिकारी नीचे दर्शाई गई तालिका के अनुसार पर्वत तथा ईंधन भत्ता प्राप्त करने का हकदार होगा :

### तालिका

स्थान	दरें
(1)	(2)
(i) 3000 मीटर और उससे अधिक उंचाई वाले स्थान	वेतन का 5% अधिकतम रु. 1150/-
(ii) 1500 मीटर और उससे अधिक परंतु 3000 मीटर से कम उंचाई वाले स्थान	वेतन का 2.5% अधिकतम रु. 500/-
iii) 3000 मीटर और उससे अधिक परंतु 1500 मीटर से कम उंचाई वाले स्थान और मडकारा नगर	वेतन का 2% अधिकतम रु. 400/-

### टिप्पणी :

- (ए) कम से कम 750 मीटर ऊंचाई पर स्थित स्थानों, जो उससे अधिक ऊंचाई वाले पर्वतों से घिरे हुए हों और जिन तक पहुंचने के लिए 1000 मीटर या उससे अधिक ऊंचाई पार करनी पड़ती हो, पर तैनात अधिकारियों को 1000 मीटर और उससे अधिक ऊंचाई वाले केन्द्रों के लिए देय दर पर पर्वत और ईंधन भत्ता दिया जाएगा।
- (बी) उक्त वर्गीकरण के अंतर्गत न आनेवाले किसी भी केन्द्र में फिलहाल दिए जाने वाले पर्वत और ईंधन भत्ते समाप्त कर दिए जाएंगे।

परंतु जो अधिकारी 1 मई, 1989 से पूर्व ऐसे केन्द्र पर तैनात था और उस तारीख के बाद भी उसी केन्द्र पर तैनात रहता है तो उसे 30 अप्रैल, 1989 को मिल रहे भत्ते की प्रमात्रा संरक्षित की जाएगी और उसी वेतनमान में उस केन्द्र में उसके तैनात रहने तक प्रति माह अदा की जाएगी।

8. कथित विनियमों में विनियम 24 के लिए निम्नलिखित विनियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:

24 चिकित्सा सहायता:

- (1) अधिकारी अपने लिए तथा उसके परिवार के संबंध में उसके द्वारा वास्तव में व्यय किए गए चिकित्सा खर्चों की प्रतिपूर्ति के लिए पात्र होगा।
- (ए) चिकित्सा व्यय: 1 फरवरी, 2004 को और उसके बाद से, अधिकारी द्वारा अपने और अपने परिवार के लिए किए गए चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति नीचे तालिका में विनिर्दिष्ट श्रेणी तथा प्रतिपूर्ति सीमा के अध्वधीन की जाएगी। इसके लिए अधिकारी को अपनी ओर से ही प्रमाणपत्र देना होगा कि उसने यह व्यय किया है और दावा की गई राशि के समर्थन में उसे खर्च का विवरण देना होगा:

तालिका

श्रेणी	प्रतिपूर्ति सीमा प्रतिवर्ष
कनिष्ठ प्रबंधन तथा मध्य प्रबंधन श्रेणी	रुपये 3750/- या व्यय की गई राशि - जो भी कम हो
वरिष्ठ प्रबंधन तथा उच्च कार्यपालक श्रेणी	रुपये 5000/- या व्यय की गई राशि - जो भी कम हो

टिप्पणी-

- (i) अधिकारी को उसके द्वारा न ली गई चिकित्सा सहायता को उस सीमा तक संचयित करने की अनुमति दी जाएगी जो ऊपर उप बंधित अधिकतम राशि के तीन गुना से अधिक न हो।
- (ii) वर्ष 2004 के लिए चिकित्सा सहायता योजना के अंतर्गत चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति 11 मास के लिए अर्थात् फरवरी 2004 से दिसंबर, 2004 तक आनुपातिक आधार पर बढ़ाई जाएगी।

स्पष्टीकरण: इस विनियम के उद्देश्य से किसी अधिकारी के परिवार से तात्पर्य होगा विनियम 3 के खंड (जी) में परिभाषित किए गए अनुसार परिवार।

- (बी) (1) जहां अस्पताल में भर्ती किया जाना आवश्यक हो ऐसे सभी मामलों में अधिकारी के मामले में 100% एवं उसके परिवार के सदस्य के मामले में 75% की सीमा तक अस्पताल प्रभार की प्रतिपूर्ति की जाएगी।



(५) 1 मई, 2005 को एवं उसके बाद से इस विनियम के अंतर्गत अस्पताल में भर्ती संबंधी व्यय की प्रतिपूर्ति कर्मकार कर्मचारी के लिए दिनांक 2 जून, 2005 के द्विपक्षीय समझौते के अंतर्गत निर्धारित अस्पताल में भर्ती संबंधी योजना की शर्तों एवं नीचे तालिका में दर्शाई गई सीमा के अधीन होगी-

### तालिका

(ए) कनिष्ठ प्रबंधन श्रेणी/वेतनमान I एवं मध्य प्रबंधन श्रेणी वेतनमान II एवं III	<p>(i)बेड प्रभार स्वयं- रु. 600/ प्रतिदिन परिवार रु.450/- प्रतिदिन</p> <p>(ii)अन्य प्रभार कर्मकार कर्मचारी को लागू अस्पताल में भर्ती संबंधी योजना के अंतर्गत निर्धारित सीमा के 125% के स्केल पर</p>
(बी) वरिष्ठ प्रबंधन श्रेणी वेतनमान IV एवं V तथा उच्च कार्यपालक श्रेणी वेतनमान VI एवं VII	<p>(i)बेड प्रभार स्वयं- रु. 800/ प्रतिदिन परिवार रु.600/- प्रतिदिन</p> <p>(ii)अन्य प्रभार कर्मकार कर्मचारी को लागू अस्पताल में भर्ती संबंधी योजना के अंतर्गत निर्धारित सीमा के 150% के स्केल पर</p>

- (2) ऊपर उप-विनियम (1) में विनिर्दिष्ट किए गए चिकित्सा लाभों (अस्पताल में भर्ती सहित) एवं उसके पूर्णतः प्रतिस्थापन में चाहे जो भी हो, निदेशक मंडल नियत तारीख पर बैंक में जो उपलब्ध हो उन चिकित्सा लाभों को बिना किसी परिवर्तन के बनाए रखने का निर्णय कर सकता है और यदि निदेशक मंडल ऐसा निर्णय करता है तो सभी अधिकारी केवल चिकित्सा लाभों (अस्पताल में भर्ती आदि सहित) की मंजूरी हेतु नियत तारीख पर उपलब्ध शर्तों के अनुसार ही चिकित्सा व्ययों की प्रतिपूर्ति प्राप्त करने के हकदार होंगे.

(3) चिकित्सा सहायता एवं अस्पताल में भर्ती संबंधी सुविधा उन अधिकारियों को भी स्वीकार्य होगी जो निलंबन के अंतर्गत हैं.

9. कथित विनियमों में विनियम 25 के लिए निम्नलिखित विनियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“ 25 आवास व्यवस्था – (1) अधिकारी बैंक द्वारा आवास उपलब्ध कराए जाने के लिए साधिकार हकदार नहीं होगा.

(2) तथापि, यदि बैंक चाहे तो, वह अधिकारी को आवास उपलब्ध करा सकता है जिसके लिए अधिकारी 01 नवम्बर, 2002 को और उसके बाद से, अपने वेतनमान के प्रथम चरण के 1.75 के बराबर राशि या आवास के लिए मानक किराये का, जो भी कम हो, भुगतान करेगा.

परंतु, जहां ऐसे आवास में फर्नीचर उपलब्ध कराया जाता है, वहां बैंक द्वारा अधिकारी से उसके वेतनमान, जिसमें वह रखा गया है, के प्रथम चरण के 0.4% के बराबर अतिरिक्त राशि वसूल की जाएगी.

परंतु, जहां बैंक द्वारा ऐसी आवास व्यवस्था उपलब्ध कराई जाती है जहां बिजली, पानी, गैस और सफाई प्रभार अधिकारी द्वारा वहन किए जाएंगे.”

10. कथित विनियमों में विनियम 41 में, उप-विनियम (1) के लिए निम्नलिखित उप विनियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्

(1) 2 जून, 2005 को और उसके बाद से अधिकारी ड्यूटी पर यात्रा करने के दौरान निम्नलिखित प्राप्त करने का हकदार होगा, अर्थात्:-

(i) कनिष्ठ प्रबंधन श्रेणी का अधिकारी रेल से प्रथम श्रेणी या ए सी 2 टायर स्लीपर में यात्रा करने का हकदार है. यद्यपि वह हवाई जहाज से (इकोनोमी श्रेणी) में यात्रा कर सकता है, यदि सक्षम प्राधिकारी व्यवसाय की आवश्यकताओं या लोक-हित की दृष्टि से ऐसी अनुमति देना है.

(ii) मध्य प्रबंधन श्रेणी का अधिकारी ट्रेन से प्रथम श्रेणी या ए सी 2 टायर स्लीपर में यात्रा करने का हकदार है या यदि यात्रा 1000 कि.मी. से अधिक हो या कम अंतर हो परंतु यदि सक्षम प्राधिकारी व्यवसाय के आकस्मिकताओं या लोक-हित की दृष्टि से ऐसी अनुमति देता है, तो वह हवाई जहाज (इकोनोमी श्रेणी) से यात्रा कर सकता है.

(iii) वरिष्ठ प्रबंधन या उच्च कार्यपालक श्रेणी का अधिकारी ए सी प्रथम श्रेणी या हवाई जहाज (इकोनोमी श्रेणी) से यात्रा करने का हकदार है.

(iv) वरिष्ठ प्रबंधन श्रेणी या उच्च कार्यपालक श्रेणी का अधिकारी जो स्थान हवाई यात्रा या रेल से जुड़े हुए न हो, वहां कार से यात्रा कर सकता है, बशर्ते अंतर 500 कि.मी. से अधिक न हो और दो स्थानों के बीच के अंतर के अधिकांश हिस्से की यात्रा हवाई जहाज या रेल से और केवल बाकी का अंतर सामान्यतया कार द्वारा कवर किया जा सकता है.

(v) अन्य किसी अधिकारी को सक्षम प्राधिकारी द्वारा व्यवसाय की आकस्मिकताओं के संबंध में उसके अपने वाहन से या टेक्सी से या बैंक के वाहन से यात्रा करने हेतु प्राधिकृत किया जा सकता है.

(बी) उप विनियम 4 में खंड (ए) के लिए निम्नलिखित खंड प्रतिस्थापित होगा, अर्थात:

(ए) विराम भत्ता- 01 जून 2005 को और उसके बाद से, नीचे तालिका में दर्शाए गए अनुसार प्रतिदिन विराम भत्ता पाने का हकदार होगा:

तालिका

अधिकारियों की श्रेणी/ वेतनमान	प्रमुख 'ए' वर्ग के नगर	क्षेत्र I	अन्य स्थान
(1)	(2)		
वेतनमान IV और उससे ऊपर के अधिकारी	रु. 600	रु. 550	रु.500
वेतनमान I/II/III के अधिकारी	रु. 550	रु. 500	रु.400

परंतु वेतनमान IV एवं उससे ऊपर के अधिकारी के मामले में चार महानगरों अर्थात् दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, चैन्नई में आउट स्टेशन कार्य हेतु प्रतिदिन विशेष भत्ता रु. 700 देय होगा.

परंतु यदि अनुपस्थिति की कुल अवधि 8 घंटे से कम, किंतु 4 घंटे से अधिक है तो ऊपर बताई गई दरों की आधी दर से विराम भत्ता देय होगा.

#### स्पष्टीकरण

विराम भत्ते की संगणना के लिए "प्रतिदिन" का अभिप्राय है 24 घंटे की अवधि या उसके बाद का कोई भी भाग, जिसकी गणना विराम यात्रा के मामलों में रिपोर्ट करने के समय तथा अन्य मामलों में प्रस्थान के लिए नियत समय से लेकर पहुंचने के वास्तविक समय तक की जाएगी. यदि अनुपस्थिति की कुल अवधि 24 घंटे से कम है तो "प्रतिदिन" से ऐसी अवधि अभिप्रेत है जो 8 घंटों से कम न हो.

11. कथित विनियमों में विनियम 42 में उप विनियम (3) के लिए निम्नलिखित विनियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"(3) 1 अप्रैल 1997 को एवं उसके बाद से अधिकारी स्थानांतरण पर पैकिंग, स्थानीय परिवहन, बेगेज़ का बीमा इत्यादि से संबद्ध व्यय के लिए नीचे तालिका में दर्शाए गए अनुसार एकमुश्त राशि प्राप्त करने का हकदार होगा, अर्थात्:-

#### तालिका

श्रेणी	एकमुश्त राशि
उच्च प्रबंधन एवं वरिष्ठ प्रबंधन	रु. 5,000.00
मध्य प्रबंधन एवं कनिष्ठ प्रबंधन	रु. 4,000.00

परंतु 1 मई 2005 को एवं उसके बाद से इस उप विनियम के प्रावधानों में ऐसा प्रभावित होगा, जैसे शब्द एवं अंक रु. "5000" एवं रु. "4000" क्रमशः "8750" एवं रु. "7000" से प्रतिस्थापित किए गए हों.

12. कथित विनियमों में विनियम 44 के लिए निम्नलिखित विनियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात:-

**"44 अवकाश यात्रा रियायत:**

- (1) चार वर्षों के प्रत्येक खंड के दौरान अधिकारी दो वर्षों के प्रत्येक खंड में एक बार अपने गृह नगर (होम टाउन) की यात्रा के लिए अवकाश यात्रा रियायत सुविधा का पात्र होगा. विकल्पतः वह दो वर्षों के एक खंड में अपने गृह नगर और दूसरे खंड में भारत में किसी भी स्थान की सबसे कम दूरी के मार्ग द्वारा यात्रा कर सकता है.
- (2) अधिकारी यथास्थिति चार वर्ष एवं 2 वर्षों के किसी ब्लॉक के दौरान किसी भी समय विकल्प का प्रयोग करते हुए छुट्टी यात्रा रियायत (गृह नगर की यात्रा के अलावा) का परित्याग कर सकता है और उस सीमा तक नकदीकरण ले सकता है, जिसके लिए वह क.प्र.श्रे/व. एवं म.प्र. श्रे वेतनमान II और III के लिए 4500 कि.मी (एक तरफा) तथा व.प्र.श्रे में वेतनमान IV एवं उच्च श्रेणी के लिए 5500 कि. मी. (एक तरफा) तक के अंतर के लिए (ट्रेन से यात्रा हेतु) उसकी पात्रता के अनुसार किराये के 75% की राशि के बराबर की राशि प्राप्त कर सकता है और अपनी अवकाश यात्रा रियायत के नकदीकरण का विकल्प चुनने के लिए यह सुविधा लेते समय उस ब्लॉक या अवधि में एक बार दावा कर सकता है तथा ऐसी अवकाश यात्रा रियायत के नकदीकरण का लाभ उठाने के साथ अर्जित अवकाश के नकदीकरण का लाभ उठा सकता है.
- (3) अवकाश किराया रियायत के लिए अधिकारी उसी साधन और श्रेणी का उपयोग कर सकता है जिससे कि वह स्थानांतरण पर यात्रा करने का पात्र है और अधिकारी द्वारा अवकाश किराया रियायत के उपयोग की अन्य शर्तें एवं निबंधन निदेशक मंडल द्वारा समय-समय पर निश्चित निबंधन एवं शर्तें होंगी.
- (4) चार वर्ष में एक बार जब अधिकारी अवकाश यात्रा रियायत का लाभ उठाता है, तब उसे एक बार में 30 दिनों तक के अर्जित अवकाश को अभ्यर्जित करने एवं उनका नकदीकरण प्राप्त करने की अनुमति करने की अनुमति दी जा सकती है या जब वह दो वर्ष के एक ब्लॉक में अपने गृहनगर या अन्य ब्लॉक में भारत में किसी भी स्थान पर यात्रा करता है, उसे प्रत्येक ब्लॉक में अधिकतम 15 दिनों या एक ब्लॉक में 30 दिनों तक के अर्जित अवकाश के नकदीकरण की अनुमति दी जा सकती है और छुट्टी नकदीकरण के प्रयोजन से जिस मास के दौरान वह अवकाश यात्रा रियायत का लाभ उठाता है, उस मास के लिए उसे सभी परिलब्धियां स्वीकार्य होंगी.

परंतु अधिकारी को अपने विकल्प से प्रधानमंत्री राहत निधि में दान देने हेतु एक दिन के अतिरिक्त अर्जित अवकाश के नकदीकरण की अनुमति होगी, वशर्ते वह बैंक को यह राशि निधि में भेजने हेतु प्राधिकृत करते हुए इस आशय का पत्र बैंक को देता है. "

**देना बैंक (अधिकारी) सेवा विनियम 1979 की अनुसूची  
(विनियम 23 का उप विनियम (2) देखें)**

1 नवम्बर 2002 को एवं उसके बाद अधिकारी नीचे तालिका में दर्शाए गए अनुसार, उस समय तक विशेष क्षेत्र भत्ता प्राप्त करने का हकदार होगा, जब तक कि ये वापिस नहीं ले लिए जाते अथवा पूर्णतः या अंशतः परिवर्तित नहीं किए जाते हैं, अर्थात:-

**तालिका**

क्रम सं.	वे स्थान, जहां भत्ता देय है	देय भत्ते की दरें	
		वेतन रु.10,000 से रु.14,000	वेतन रु.14,001 एवं अधिक
1	मिजोरम (क) मिजोरम का चमटुईपुई जिला तथा मिजोरमके लुंगलेई जिले के लुंगलेई शहर से 25 किमी से अधिक दूरी वाले क्षेत्र (ख) पूरे लुंगलेई जिले में, लुंगलेई शहर से 25 किमी से दूर वाले क्षेत्र छोड़कर (ग) मिजोरम का पूरा आइजवाल जिला	रु. 1000  800  600	रु. 1300  1050  750
2	नागालैण्ड	800	1050
3	अंदमान एवं निकोबार द्वीप समूह (क) दक्षिण अंदमान (पोर्ट ब्लेयर सहित) (ख) उत्तर एवं मध्य अंदमान, लिटल अंदमान तथा नाकोण्डम द्वीप समूह	800  1000	1050  1300
4	सिक्किम	1000	1300
5	लक्ष्य द्वीप द्वीप समूह	1000	1300
6	असम	160	200
7	मेघालय	160	200

क्रम सं.	वे स्थान, जहां भत्ता देय है	देय भत्ते की दरें	
		वेतन रु.10,000 से रु.14,000	वेतन रु.14,001 एवं अधिक
8	त्रिपुरा (क) त्रिपुरा के कठिन क्षेत्र (ख) कठिन क्षेत्रों को छोड़कर पूरा त्रिपुरा	800 600	1050 750
9	मणिपुर	600	750
10	अरुणाचल प्रदेश (क) अरुणाचल प्रदेश के कठिन क्षेत्र (ख) कठिन क्षेत्र के अलावा समस्त अरुणाचल प्रदेश	1000 800	1300 1050
11	जम्मू एवं कश्मीर (1) कठुआ जिला (क) नियाबत बानी (ख) लोही (ग) मलहार (घ) मक्चोड़ी 2. (ए) उधमपुर जिला (i) दादू बसंतगढ़ (ii) लेंडर भमाग इलाका (iii) ठकराकोटे (iv) नगोटे (बी) 2(सी) में शामिल किए गए क्षेत्रों को छोड़ कर तहसील महोर के सभी क्षेत्र (सी) कम्बन की ओर से गोयल तक तथा कीसू की ओर से अरनास तक के तहसील मोहरे के क्षेत्र	1000      1000 1000 800	1300      1300 1300 1050

क्रम सं.	वे स्थान, जहां भत्ता देय है	देय भत्ते की दरें	
		वेतन रु.10,000 से रु.14,000	वेतन रु.14,001 एवं अधिक
	(3) डोडा जिला (क) किश्तवार तहसील में पाडेर एवं नियाबत नौगाम	1000	1300
	(4) लेह जिला लेह जिले के सभी स्थान	1000	1300
	(5) बारामुला जिला (क) समस्त गुरेज-नियाबत, तंगदार सब डिविजन तथा केरत इलाका (ख) मचिल	1000	1300
	(6) पुंछ तथा राजौरी जिला पुंछ और राजौरी नगरों को छोड़कर अन्य क्षेत्र तथा सुंदरबनी तथा अन्य शहरी क्षेत्र	800 600	1050 750
	(7) उपरोक्त (1) से (6) के अलावा अन्य क्षेत्र जो वास्तविक नियंत्रण रेखा से 8 कि.मी. से कम दूरी पर है या वह क्षेत्र जो समय समय पर राज्य सरकार द्वारा उनके स्टाफ के लिये बार्डर भत्ते के रूप में घोषित किया जाता है	600	750
12	हिमाचल प्रदेश  1. चंबा जिले  1 (ए) पांगी तहसील  1.(बी) भरमौर तहसील के निम्नलिखित पंचायत एवं गांव  (i) पंचायत: बड़गांव, बजोल, देव कुगती, नायगांव एवं तुंडाह	  1000  800	  1300  1050



क्रम सं.	वे स्थान, जहां भत्ता देय है	देय भत्ते की दरें	
		वेतन रु.10,000 से रु.14,000	वेतन रु.14,001 एवं अधिक
	(ii) गांव: ग्राम पंचायत जगत का घुदु, ग्राम पंचायत चुहाटा का कनारसी		
	2. ऊपर भाग I बी में शामिल पंचायत एवं गावों को छोड़ कर भारमोर तहसील		
	3. भटियाट तहसील में झांदरु पंचायत, चुराह तहसील, दलहौजी शहर (बानीखेत प्रोपर सहित)	600	750
	(2) किन्नौर जिला:		
	(ए) असरांग, चितकुल एवं हैंगोकुनो/चारंग पंचायत, 15/20 क्षेत्र जिनमें छोटा खम्बा, नाथपा एवं रुपी, पूह सब डिविज़न, शामिल है, ऊपर दर्शाए गए पंचायत क्षेत्रों को छोड़ कर.	1000	1300
	(बी) ऊपर (ए) में शामिल क्षेत्रों को छोड़ कर पूरा जिला	600	750
	(3) कुलु जिला		
	3(ए) निरमंद तहसील के 15/20 क्षेत्र, जिनमें खारगा, कुश्वार एवं सारगा के ग्राम पंचायत शामिल हैं	1000	1300

क्रम सं.	वे स्थान, जहाँ भत्ता देय है	देय भत्ते की दरें	
		वेतन रु.10,000 से रु.14,000	वेतन रु.14,001 एवं अधिक
	3(बी) आउटर-सेरज (निरमंद तहसील के जकात- खाना एवं बुरोव गांवों को छोड़ कर) एवं पूरा जिला (आउटर सेरज क्षेत्र एवं पंदरवीस परगना को छोड़ कर परंतु निरमंद तहसील के जकात-खाना एवं बुरोव गांव सहित)	600	750
	(4) लाहौल एवं स्पिति जिला:  लाहौल एवं स्पिति जिले के समस्त क्षेत्र	1000	1300
	(5) शिमला जिला:  (ए) कूट, लबाना-सदाना, सारपारा एवं चदी-ब्रांदा पंचायत सहित रामपुर तहसील का 15/20 क्षेत्र	1000	1300
	(बी) दोन्द्रा-कवार तहसील, रामपुर में दारकली ग्राम पंचायत काशापाठ तहसील एवं परगना सारहान के मुनिश, घोरी एवं चैबिस	800	1050
	(सी) चोपल तहसील एवं घोरिस, पंजगांव, पत्सनौ, नौबिस एवं तीन कोटी ऑफ परगना सारहन, तकलेश क्षेत्र की देओठी ग्राम पंचायत, परगना बाराबीस, रामपुर तहसील के परगना रामपुर का कस्बा रामपुर एवं घोरी एनओजी, □ शिमला शहर एवं सबर्ब (धल्ली, जतोग, कसुम्पति, मासोब्रा, तारादेवी एवं टूटू	600	750

क्रम सं.	वे स्थान, जहां भत्ता देय है	देय भत्ते की दरें	
		वेतन रु.10,000 से रु.14,000	वेतन रु.14,001 एवं अधिक
	(6) कांगरा जिला:		
	(ए) बारा भांगल एवं छोटा भांगल के क्षेत्र	800	1050
	(बी) कांगरा जिले का धरमशाला शहर एवं निम्नलिखित कार्यालय जो म्यूनिसिपल सीमा से बाहर है परंतु धरमशाला शहर में शामिल किए गए हैं: महिला आईटीआई, दारी, मेकंसिया वर्कशॉप, रामनगर, चाइल्ड वेलफेयर एवं टाऊन एंड कंट्री प्लानिंग कार्यालय, साकोह, कांगरा मिल्क सप्लाय स्कीम, दुगियार, एच आर टी सी वर्कशॉप, साधेर, ज़ोनल मलारिया ऑफिस, दारी, फॉरिस्ट कार्पोरेशन ऑफिस, शामनगर, टी फैक्टरी, दारी आईपीएच सब डिविज़न, दान सेटलमेंट ऑफिस, शामनगर, बिनवा प्रोजेक्ट, शामनगर, ऑफिस, जेरसी फार्म, बनुरी, सेरीकल्चर, ऑफिस/इंडो-जर्मन एग्रिकल्चर वर्कशॉप/एचपीपीडबल्यूडी डिविज़न, बुंदला, इलेक्ट्रिक सब डिविज़न, लोहना, डीपीओ, कार्पोरेशन, बुंदला, इलेक्ट्रिकल एचपीएसईई डिविज़न, घुग्गर	600	750
	(7) मंडी जिला		
	छुहार वेली ऑफ जोगिन्दरनगर तहसील, थुंग पंचायत	600	750

क्रम सं.	वे स्थान, जहां भत्ता देय है	देय भत्ते की दरें	
		वेतन रु.10,000 से रु.14,000	वेतन रु.14,001 एवं अधिक
	<p>तहसील-बागरा, चन्नी, छोट्थारगरागुसैन, गट्टू, गरयास, जानेहिल, जरयार, जोहर, कल्हनी, कलवां, खोलनाल, लोठ, सिलिबागी, सोमचन, थचधार, ताची, थाना, धर्मपुर ब्लॉक-बिन्गा पंचायत. कमलाह, सकलाना, तन्यार ताराखोलाह, पंचायत-कारसोग, तहसील बलीधर, बागरा, गोपालपुर, खाजोल, महोग, मेहुडी, मंज पेखी साइंज, सरहान एवं तेबान, पंचायत-सुंदरनगर, तहसील-बोही, बटवारा, धनयारा, पौरा, कोठी, सेरी एवं शोजा</p> <p>(8) सिरमौर जिला:</p> <p>(ए) बानी, बखाली पंचायत (पछाड तहसील), भारोग, भेनेरी (पौंता तहसील). विरला (नाहन तहसील) दिब्बर (पछाड तहसील) एवं थाना कसोगा (नाहन तहसील)</p> <p>(बी) थंसगिरि ट्रैक्ट</p> <p>(9) सोलन जिला:</p> <p>मंगल पंचायत</p> <p>(10) ऊपर (1) से (9) में शामिल नहीं है ऐसे बाकी के सभी क्षेत्र</p>	<p>600</p> <p>600</p> <p>160</p>	<p>750</p> <p>750</p> <p>200</p>

क्रम सं.	वे स्थान, जहां भत्ता देय है	देय भत्ते की दरें	
		वेतन रु.10,000 से रु.14,000	वेतन रु.14,001 एवं अधिक
13	उत्तर प्रदेश: चमोली, पिथोरगढ़ और उत्तरकाशी के अंतर्गत के क्षेत्र  2(ए) जिला पिथोरगढ़ और उत्तरकाशी के अन्य क्षेत्र (उत्तरकाशी के जिला मुख्यालयों सहित) 2(बी) चंपावत जिला (लोहाघाट के क्षेत्र सहित)	1000	1300
14	उत्तरांचल:  रुद्रप्रयाग एवं चंपावत जिले के अंतर्गत के क्षेत्र	800	1050

आर. श्रीधरन, महा प्रबंधक (मा.सं.प्र.)

[ विज्ञापन III/4/130/11-असा. ]

**टिप्पणी :** मुख्य विनियम सरकारी राजपत्र में दिनांक 1-7-1979 को प्रकाशित हुए थे ।

### DENA BANK NOTIFICATION

New Delhi, the 25th October, 2010

**F. No. IR/696/2010.**—In exercise of the powers conferred by Section 19, read with sub-section (2) of Section 12 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 (5 of 1970), the Board of Directors of Dena Bank in consultation with the Reserve Bank of India and with the previous sanction of the Central Government, hereby makes the following regulations further to amend the Dena Bank (Officers') Service Regulations, 1979, namely :—

1. (1) These regulations may be called the Dena Bank (Officers') Service (Amendment) Regulations, 2010.
  - (2) They shall come into force with effect from the 2nd day of June, 2005 except wherever stated otherwise in the respective regulations.
  2. In the Dena Bank (Officers') Service Regulations, 1979, (hereinafter referred as the said regulations), in regulation 3, —
    - (i) for clause (g), the following clause shall be substituted, namely, —  
'(g) "Family" means the spouse of the officer (who is not an employee of the Bank), wholly dependent unmarried children (including dependent step and legally adopted children) and parents ordinarily residing with and wholly dependent on the officer;';
    - (ii) for clause (o), the following clause shall be substituted, namely :—  
'(o) "Wholly dependent children or parents" mean children or parents having an income not exceeding Rs. 2,550 per month.'
- Note :—** If the income of one of the parents exceeds Rs. 2,550 per month or the aggregate income of both the parents exceeds Rs. 2,550 per month, both the parents shall not be considered as wholly dependent on the employee;'

3. In the said regulations, in regulation 4, for sub-regulation (4), the following sub-regulations shall be substituted, namely:-

‘(4) On and from the 1<sup>st</sup> day of November 2002, the scales of pay specified against each grade shall be as under: -

(a) Top Executive Grade:

$$\text{Scale VII} = \text{Rs.} 29340 - \frac{680}{2} - 30700 - \frac{900}{1} - 31600 - \frac{1000}{1} - 32600$$

$$\text{Scale VI} = \text{Rs.} 26620 - \frac{680}{4} - 29340$$

(b) Senior Management Grade:

$$\text{Scale V} = \text{Rs.} 24140 - \frac{620}{4} - 26620$$

$$\text{Scale IV} = \text{Rs.} 20480 - \frac{560}{1} - 21040 - \frac{620}{5} - 24140$$

(c) Middle Management Grade:

$$\text{Scale III} = \text{Rs.} 18240 - \frac{560}{5} - 21040 - \frac{620}{2} - 22280$$

$$\text{Scale II} = \text{Rs.} 13820 - \frac{500}{1} - 14320 - \frac{560}{10} - 19920$$

(d) Junior Management Grade:

$$\text{Scale I} = \text{Rs.} 10000 - \frac{470}{6} - 12820 - \frac{500}{3} - 14320 - \frac{560}{7} - 18240.$$

Note: Every officer who is governed by the scales of pay as in force as on 31<sup>st</sup> October, 2002 shall be fitted in the scale of pay set out as in this sub-regulation as on 1<sup>st</sup> November, 2002 on stage to stage basis, i.e. on corresponding stages from first stage onwards in the respective scales and the increments shall fall on the anniversary date as usual except where provided otherwise;

(4A) Nothing in sub-regulations (1), (2), (3) and (4) shall be construed as requiring the bank to have at all times, officers serving in all these grades.’

4. In the said regulations, for regulation 5, the following regulation shall be substituted, namely: -

‘5. Increments. – (1) Subject to the provisions of sub-regulation (4) of regulation 4, on and from the 1<sup>st</sup> day of November, 2002, the increments shall be granted subject to the following conditions, namely: -

- (a) The increments specified in the scales of pay set out in sub-regulation (4) of regulation 4 shall, subject to the sanction of the Competent Authority, accrue on an annual basis and shall be granted on the first day of the month in which these fall due;
- (b) Officers in Scale I and Scale II, one year after reaching the maximum in their respective scales, shall be granted further increments including stagnation increment(s) in the next higher scale only as specified in clause (c) below subject to their crossing the efficiency bar as per guidelines of the Government;
- (c) Officers including those referred to in clause (b) above who reach the maximum of the Middle Management Grade Scales II and III shall draw stagnation increment(s) for every three completed years of service after reaching the last stage of the Scale II or Scale III, as the case may be, subject to a maximum of two such increments of Rs.560 each for officers in the last stage of Scale II and one such increment of Rs.620 for officers in the last stage of Scale III:

Provided that on and from the 1<sup>st</sup> day of November, 1994 the officers in substantive Scale III i.e. those who are recruited in or promoted to Scale III shall be eligible for second stagnation increment three years after having received the first stagnation increment:

Provided further that such increment/s in the next higher scale/stagnation increment/s shall not be allowed to an officer who refuses promotion when offered.

Note: Grant of such increments in the next higher scale shall not amount to promotion. Officers even after receipt of such increments shall continue to get privileges, perquisites, duties, responsibilities or posts of their substantive Scale I or Scale II as the case may be.

- (2) An additional increment each shall be granted in the scale of pay for passing Part I of Certified Associate of Indian Institute of Bankers/Junior Associate of Indian Institute of Banking and Finance and Part II of Certified Associate of Indian Institute of Bankers Examination.

Explanation: (a) in the case of an officer who has passed Part I or Part II of Certified Associate of Indian Institute of Bankers Examination as an officer before the appointed date, the additional increment, or increments as the case may be, shall be given effect to from the appointed date provided that he has not received any increment or received only one increment, for passing both parts of the said Examination.

(b) on and from the 1<sup>st</sup> day of November, 1987, officers who reach or have reached the maximum in the pay scale and are unable to move further except by way of promotion shall subject to Government guidelines, if any, be granted Professional Qualification Allowance in lieu of additional increments as specified in the Table below:

TABLE

Those who have passed: only Part I of Certified Associate of Indian Institute of Bankers	(i) Rs.100 per month after one year of which Rs.75 shall rank for superannuation benefits.
Those who have passed: both Parts of Certified Associate of Indian Institute of Bankers	(i) Rs.100 per month after one year, of which Rs.75 shall rank for superannuation benefits;
	(ii) Rs.250 per month after two years, of which Rs.200 shall rank for superannuation benefits.

(c) on and from 1<sup>st</sup> day of November, 1994, other things being equal, the quantum of Professional Qualification Allowance shall stand revised as specified in the table below: -



TABLE

Those who have passed: only Part I of Certified Associate of Indian Institute of Bankers	(i) Rs.120 per month after one year on reaching top of the scale.
Those who have passed: both parts of Certified Associate of Indian Institute of Bankers	(i) Rs.120 per month after one year on reaching top of the scale; (ii) Rs.300 per month after two years on reaching top of the scale:

Provided that officers who are eligible to draw Fixed Personal allowance in terms of clause (b) of sub-regulation (3) of regulation 5, shall draw Professional Qualification Allowance one year/two years after receipt of such Fixed Personal Allowance respectively for Part I and II as the case may be.

(d) on and from the 1<sup>st</sup> day of November, 1999, other things being equal, the quantum of Professional Qualification Pay shall stand revised as specified in the table below: -

TABLE

Those who have passed Junior Associate of Indian Institute of Bankers or Part I of Certified Associate of Indian Institute of Bankers:	(i) Rs.150 per month after one year on reaching maximum of the scale.
Those who have passed Junior Associate of Indian Institute of Bankers and Certified Associate of Indian Institute of Bankers or both parts of Certified Associate of Indian Institute of Bankers:	(i) Rs.150 per month after one year on reaching maximum of the scale; (ii) Rs.360 per month after two years on reaching maximum of the scale:

Provided that officers who are in Scale I and Scale II and are granted further increments in the next higher scale as in clause (b) of sub-regulation (1) shall draw Professional Qualification Pay after one or two years, as the case may be, on reaching the maximum in such higher scales.

(e) on and from the 1<sup>st</sup> day of November, 2002, other things being equal, the quantum of Professional Qualification Pay shall stand revised as specified in the table below: -

TABLE

Those who have passed Junior Associate of Indian Institute of Bankers or Part I of Certified Associate of Indian Institute of Bankers	(i) Rs.300 per month after one year on reaching maximum of the Scale.
Those who have passed both parts of Certified Associate of Indian Institute of Bankers	(i)Rs.300 per month after one year on reaching maximum of the Scale; (ii)Rs.750- per month after two years on reaching maximum of the Scale:

Provided that officers who are in Scale I and Scale II and are granted further increments in the next higher scale as specified in clause (b) of sub-regulation (1) shall draw Professional Qualification Pay after one or two years, as the case may be, on reaching the maximum in such higher scales.

Note : (i) if an officer who is in receipt of Professional Qualification Pay is promoted to next higher scale, he shall be granted, on fitment in such higher scale, additional increment(s) for passing Junior Associate of Indian Institute of Bankers/Certified Associate of Indian Institute of Bankers to the extent increments are available in the scale and if no increments are available in the scale, the officer shall be eligible for Professional Qualification Pay in lieu of increment(s).

(ii) on and from the 1<sup>st</sup> day of November, 1994, Professional Qualification Allowance or Professional Qualification Pay, as the case may be, shall rank for Dearness Allowance, House Rent Allowance and superannuation benefits.

(iii) an officer shall not be eligible for Professional Qualification Pay as above if he refuses to accept promotion when offered.

(iv) if an officer acquiring Junior Associate of Indian Institute of Bankers or Certified Associate of Indian Institute of Bankers (either or both parts) qualifications after reaching the maximum of the scale of pay, shall be granted from the date of acquiring such qualification the first installment of Professional Qualification Pay and the release of subsequent installments of Professional Qualification Pay shall be with reference to the date of release of first installment of Professional Qualification Pay.

(v) if an officer, as on the 2<sup>nd</sup> day of June, 2005 has already acquired any of the said qualifications referred to in clause (iv) and has not earned any increment or Professional Qualification Pay on account of acquiring such qualification/s, he shall be, with effect from the 1<sup>st</sup> day of November, 2002 or the date of acquiring such qualification/s, whichever is later, released Professional Qualification Pay as provided herein above.

- (3)(a) all officers who are in the bank's permanent service as on the 1<sup>st</sup> day of November, 1993 shall get one advance increment in the scale of pay and officers who are on probation on the 1<sup>st</sup> day of November 1993 will get one advance increment one year after the confirmation.

Note: There shall be no change in the date of annual increment because of advance increment.

- (b) an officer who is at the maximum of the scale or who is in receipt of stagnation increment(s) as on 1<sup>st</sup> day of November, 1993, will draw a Fixed Personal Allowance from the 1<sup>st</sup> day of November, 1993 which shall be equivalent to an amount of last increment drawn plus dearness allowance payable thereon as on 1<sup>st</sup> day of November, 1993, plus House Rent Allowance, at such rates as applicable in terms of regulation 22 and the Fixed Personal Allowance together with House Rent Allowance, if any, as specified in the table below shall remain valid till further revised: -

TABLE

Increment Component	Dearness Allowance as on 1.11.1993 on the increment component	Total Fixed Personal Allowance payable where bank's accommodation is provided
(A) Rs.	(B) Rs.	(C) Rs.
230	5.79	236
250	6.30	257
300	7.56	308
400	10.08	411

- (c) on and from the 1<sup>st</sup> day of November, 1999 other things being equal, the Fixed Personal Pay with House Rent Allowance, if any, shall be as specified in the table below: -

TABLE

Increment Component	Dearness Allowance as on 1.11.1997 on the increment component	Total Fixed Personal Allowance payable where bank's accommodation is provided
(A) Rs.	(B) Rs.	(C) Rs.
340	4.28	345
380	4.78	385
420	5.29	426
600	7.56	608

- (d) on and from the 1<sup>st</sup> day of November 2004, other things being equal, Fixed Personal Pay together with House Rent Allowance, if any, shall be as specified in the table below and shall remain frozen for the entire period of service: -

TABLE

Increment Component	Dearness Allowance as on 01.11.2002 on the increment components	Total Fixed Personal Pay payable where bank's accommodation is provided
(A) Rs.	(B) Rs.	(C) Rs.
560	23	583
620	25	645
680	28	708
1000	41	1041

Note: (i) Fixed Personal Allowance/Fixed Personal Pay as indicated under Column (C) of the tables in clauses (b), (c) and (d) of sub-regulation (3) of regulation 5 shall be payable to those officers who are provided with bank's accommodation.

(ii) Fixed Personal Allowance/Fixed Personal Pay for officers eligible for House Rent Allowance shall be (A)+(B)+House Rent Allowance as indicated in clauses (b), (c) and (d) of sub-regulation (3) of regulation 5 drawn by the concerned officer on the increment component of the relevant scale of pay as specified in sub-regulation (2) and (3) of regulation 4 is earned.

(iii) on and from the 1<sup>st</sup> day of November, 1999 there shall be no change in the schedule of release of Professional Qualification Pay as in Explanation (c) of sub-regulation (2) on account of release of Fixed Personal Pay:

Provided that where any instalment of Professional Qualification Pay which on account of the earlier provisions has been shifted by a year and is scheduled for release on or after to 1<sup>st</sup> day of November, 1999, it shall be released to the officer on and from this date and second instalment of Professional Qualification Pay, if any, shall be released on the 1<sup>st</sup> day of November, 2000.

(iv) the increment component of Fixed Personal Allowance/Fixed Personal Pay shall rank for superannuation benefits.

(e) an officer who has earned the advance increment as specified in clause (a) above shall draw the quantum of Fixed Personal Allowance/Fixed Personal Pay as mentioned in clauses (b), (c) or (d) above, one year after reaching the maximum of the scale”:

5. In the said regulations, in regulation 21, after sub-regulation (3), the following sub-regulation shall be inserted, namely: -

“(4) On and from the 1<sup>st</sup> day of November, 2002, Dearness Allowance Scheme shall be as under:

(a) dearness allowance shall be payable for every rise or fall of 4 points over 2288 points in the quarterly average of the All India Average Working Class Consumer Price Index (General) Base 1960 = 100.

(b) during the period from the 1<sup>st</sup> day of November, 2002 to 31<sup>st</sup> day of January, 2005, dearness allowance shall be payable as per the following rates :-

(i) 0.18% of ‘pay’ upto Rs.9,650 plus

(ii) 0.15% of ‘pay’ above Rs.9,650 and upto Rs.15,350  
plus

(iii) 0.09% of ‘pay’ above 15,350 and upto Rs.16,350 plus

(iv) 0.04% of ‘pay’ above Rs.16,350

- (c) on and from the 1<sup>st</sup> day of February, 2005, dearness allowance shall be payable at 0.18% of pay.

Note: (A) "Pay" for the purpose of Dearness Allowance shall mean basic pay including Stagnation Increments.

(B) (Professional Qualification Allowance or Professional Qualification Pay as specified in Explanations (c), (d) and (e) to sub-regulation (2) of regulation 5 shall rank for dearness allowance.'

6. In the said regulation, for regulation 22, the following regulation shall be substituted, namely:-

'22. House Rent Allowance – (1) (a) on and from the 1<sup>st</sup> day of November, 1999 where an officer is provided with residential accommodation by the Bank, a sum equal to 2.5% of the basic pay in the first stage of the scale of pay in which he is placed or the standard rent for the accommodation, whichever is less, will be recovered from him.

(b) where an officer is not provided any residential accommodation by the Bank, he shall be eligible on and from the 1<sup>st</sup> day of November, 1999 the House Rent Allowance as specified in the Table below, namely: -

TABLE

Where the place of work is in (1)	HRA payable shall be (2)
(i) Major 'A' class Cities specified as such from time to time in accordance with the guidelines of the Governemnt and Project Area Centres in Group 'A'.	9% of the pay per month.
(ii) Places in Area I and Project Area Centres in Group 'B'.	8% of the pay per month.
(iii) Area II i.e. all places not covered by (i) and (ii) above	7% of the pay per month.

Provided that if an officer produces a rent receipt, the House Rent Allowance payable to him shall be the actual rent paid by him for his residential accommodation in excess over 2.5% of the pay in the first stage of the scale of

pay in which he is placed or 150% of the House Rent Allowance payable as per column (2) of the above table, whichever is lower.

- (2)(a) On and from the 1<sup>st</sup> day of November, 2002, where an officer is provided with residential accommodation by the Bank, a sum equal to 1.75% of the basic pay in the first stage of the scale of pay in which he is placed or the standard rent for the accommodation, whichever is less, will be recovered from him.
- (b) where an officer is not provided any residential accommodation by the bank, he shall be eligible on and from the 1<sup>st</sup> day of November, 2002 the House Rent Allowance as specified in the table below, namely: -

TABLE

	Where the place of work is in	House Rent Allowance payable shall be
	(1)	(2)
(i)	Major "A" Class Cities and Project Area Centres in Group A	8.5% of Pay
(ii)	Other places in Area I and Project Area Centres in Group B	7.5% of Pay
(iii)	Other places	6.5% of Pay

Provided that if an officer produces a rent receipt, the House Rent Allowance payable to him/her shall be the actual rent paid by him/her for the residential accommodation in excess over 1.75% of Pay in the first stage of the scale of pay in which he/she is placed with a maximum of 150% of the House Rent Allowance payable as per column (2) of the above Table.

- (3) Where an officer resides in his own accommodation he shall be eligible for a House Rent Allowance on the same basis as mentioned in proviso to clause (b) of sub-regulation (1) and clause (b) of sub-regulation (2) as if he was paying by way of monthly rent a sum equal to one twelfth of the higher of (A) or (B) below:-

## (A)

The aggregate of: -

- (i) Municipal taxes payable in respect of the accommodation; and
- (ii) 12% of the capital cost of the accommodation including the cost of the land and if the accommodation is part of a building, the proportionate share of the capital cost of the land attributable to that accommodation, excluding the cost of special fixtures, like air conditioners; or

## (B)

The annual rental value taken for municipal assessment of the accommodation.

Explanation:-

- (1) For the purpose of this regulation “standard rent” means: -
  - (a) in the case of any accommodation owned by the Bank, the standard rent calculated in accordance with the procedure for such calculation in vogue in the Government;
  - (b) where accommodation has been hired by the bank, contractual rent payable by the bank or rent calculated in accordance with the procedure specified in (A) above, whichever is lower.
- (2) “Pay” for the purpose of House Rent Allowance shall mean basic pay including stagnation increments.
- (3) Professional Qualification Allowance or Professional Qualification Pay as the case may be, shall rank for House Rent Allowance with effect from the 1<sup>st</sup> day of November, 1994.
- (4) For the purpose of sub-regulations (1) and (2) of this regulation and regulation 23, Area I and Area II shall mean as under :-  
  

Area I	-	Places with a population of more than 12 lakhs
Area II	-	All places not included in Area – I.’.



7. In the said regulations, for regulation 23, the following regulation shall be substituted, namely :-

**23. Other Allowances:**

- (1) On and from the 1<sup>st</sup> day of November, 2002, an officer shall be eligible for the City Compensatory Allowance as specified in the table below, namely,

**TABLE**

Places	Rates
(1)	(2)
(a) Places in Area I and in the State of Goa	4% of basic pay subject to a maximum of Rs.540 per month
(b) Places with population of 5 lakhs and over and State Capitals and Chandigarh, Pondicherry and Port Blair not covered by (a) above.	3% of basic pay subject to a maximum of Rs.375 per month.
(c) Other places	Nil

- (2) On and from the 1<sup>st</sup> day of November, 2002, the rates of special area allowance shall be as specified in the Schedule to these regulations.
- (3) On and from the 1<sup>st</sup> day of November, 2002, if an officer is serving in an area to be specified as Project Area falling under Group A or Group B, he shall be eligible for a Project Area Compensatory Allowance at the rate of Rs.210 per month or Rs.185 per month according to the classification of area as Group A or Group B.
- (4) On and from the 1<sup>st</sup> day of January, 2004, if an officer is transferred from one place to another in the midst of an academic year and if he has one or more children studying in school or college, in the former place, he shall be eligible for a mid-academic year transfer allowance at the rate of Rs.500 per month from the date he reports to the latter place upto the end of the academic year in respect of all the children studying:

Provided that such allowance shall cease if all the children cease studying at the former place.

- (5) On and from the 1<sup>st</sup> day of June, 2005, if an officer is deputed to serve outside the bank, he may opt to receive the emoluments attached to the post to which he is deputed, or he may in addition to his pay, draw a deputation allowance at the rate of 7.75% of pay subject to a maximum Rs.1500 per month and such other allowances he would have drawn had he been posted in the bank's service at that place:

Provided that where he is deputed to an organisation which is located at the same place where he was posted immediately prior to his deputation, he shall receive a deputation allowance equal to 4% of his pay subject to a maximum Rs.750 per month:

Provided further that an officer on deputation to the Training Establishment of the bank as a faculty member shall be eligible for deputation allowance at the rate of 4% of his pay subject to a maximum Rs.750 per month.

- (6) If an officer is required to officiate in a post in a higher scale for a continuous period of not less than seven days at a time or an aggregate of seven days during a calendar month, he shall receive an officiating allowance equal to 6% of his pay, pro-rata for the period for which he officiates and officiating allowance will rank as pay for the purposes of Provident Fund and Pension only:

Provided that where an officer comes to officiate in a higher scale, as a consequence solely of the review of the categorization of posts under regulation 6, he shall not be eligible for the officiating allowance for a period of one year from the date on which the review of the categorization takes effect.

- (7) If an officer is posted at a branch where books are closed on the 1<sup>st</sup> April and the 30<sup>th</sup> September, a closing allowance of Rs.250 for each of the two closings.

- (8) On and from the 1<sup>st</sup> day of November, 2002, if the working hours during a day are split with minimum interval of two hours, an officer shall be eligible for a Split Duty Allowance at the rate of Rs.125 per month
- (9) If an officer is required to work as custodian of a vault or locker on a holiday, he shall be eligible for a Diem Allowance at the rate to which he is entitled.
- (10) On and from the 1<sup>st</sup> day of November, 2002, an officer shall be eligible for the hill and fuel allowance as specified in the table below, namely:-

TABLE

Place	Rate
(1)	(2)
(i) Place with an altitude of 3000 metres and above	5% of pay subject to a maximum of Rs.1150 per month
(ii) Place with an altitude of 1500 metres and above but less than 3000 metres	2½% of pay subject to a maximum of Rs.500 per month
(iii) Place with an altitude of 1000 metres and above but less than 1500 metres and Mercara Town	2% of pay subject to a maximum of Rs.400 per month.

Note : (a) officers posted at places with an altitude of not less than 750 metres and which are surrounded by hills with higher altitude which cannot be reached without crossing an altitude of 1000 metres or more, shall be paid hill and fuel allowance at the same rate as is payable at centers with an altitude of 1000 metres and above.

(b) Hill and Fuel Allowance presently paid at any centre not covered by the above classification shall stand withdrawn:

Provided that in respect of an officer who was posted in such a centre prior to 1st day of May, 1989 and remains posted at that centre even after that date, the quantum of allowance which he was drawing as on the 30th day of April, 1989 shall be protected and paid to him every month till the time he remains posted at that centre in the same scale of pay.

8. In the said regulations, for regulation 24, the following regulation shall be substituted, namely:-

**'24. Medical Aid:-**

- (1) An officer shall be eligible for reimbursement of medical expenses actually incurred by him in respect of himself and his family on the following basis, namely:-

- (a) Medical Expenses:- On and from the 1<sup>st</sup> day of February, 2004 an officer shall be eligible for reimbursement of medical expenses for self and family on the strength of the officer's own certificate of having incurred such expenditure supported by a statement of accounts for the amounts claimed as specified in the table below, namely:-

TABLE

Grade	Maximum limit of reimbursement
Junior Management and Middle Management Grade	Rs.3750 or the amount incurred whichever is less
Senior Management and Top Executive Grade	Rs.5000 or the amount incurred whichever is less

Note: (i) an officer may be allowed to accumulate unavailed medical aid so as not to exceed at any time three times the maximum amount provided above.

(ii) for the year 2004 the reimbursement of medical expenses under the medical aid scheme shall be enhanced proportionately for eleven months, i.e. from February 2004 to December 2004.

Explanation : - "Family" of an officer for the purpose of this regulation shall mean the family as defined in clause (g) of regulation 3.

- (b)(i) Hospitalisation charges shall be reimbursed to the extent of 100% in the case of an officer and 75% in the case of his family members in respect of all cases which require hospitalization.

- (ii) on and from the 1<sup>st</sup> day of May, 2005, reimbursement of hospitalisation expenses to an officer under this regulation shall be in accordance with the terms and conditions of Hospitalisation Scheme laid down under the Bipartite Settlement dated the 2<sup>nd</sup> day of June, 2005 for workmen employees, subject to the limits as specified in the table below, namely:-

TABLE

(a) Junior Management Grade Scale I and Middle Management Grade Scales II and III.	<p>(i) Bed Charges</p> <p>Self – Rs.600 per day.</p> <p>Family – Rs.450 per day.</p> <p>(ii) Other charges –</p> <p>At the scale of 125% of the limits laid down under the Hospitalisation Scheme applicable to workmen employees.</p>
(b) Senior Management Grade Scales IV and V and Top Executive Grade Scales VI and VII.	<p>(i) Bed Charges</p> <p>Self – Rs.800 per day.</p> <p>Family – Rs.600 per day.</p> <p>(ii) Other charges –</p> <p>At the scale of 150% of the limits laid down under the Hospitalisation Scheme applicable to workmen employees.</p>

- (2) Notwithstanding the medical benefits (including hospitalization etc.) specified in sub-regulation (1) above, and in complete substitution of the same, the Board may decide to retain in an unaltered form medical benefits (including hospitalization, etc.) as available in the Bank on the appointed date and if the Board so decides, all officers shall be eligible for reimbursement of medical expenses only as per the terms and conditions obtaining in the bank on the appointed date for grant of medical benefits (including hospitalization, etc.)

(3) Medical Aid and Hospitalisation facilities shall also be admissible to the officers who are placed under suspension.

9. In the said regulations, for regulation 25, the following regulation shall be substituted, namely:-

‘25. Residential Accommodation.- (1) No officer shall be entitled as of right to be provided with residential accommodation by the Bank.

(2) It shall, however, be open to the Bank to provide residential accommodation to an officer on payment by the officer, on and from the 1st day of November, 2002, a sum equal to 1.75% of the basic pay in the first stage of the scale of pay in which he is placed or the standard rent for the accommodation, whichever is less:.

Provided that where the officer is provided with furniture at such residence, a further sum equal to 0.4% of basic pay in the first stage of the scale of pay in which he is placed, will be recovered by the Bank from him:

Provided further that, where such residential accommodation is provided by the bank, the charges for electricity, water, gas and conservancy shall be borne by the officer.’.

10. In the said regulations, in regulation 41, - for sub-regulation (1), the following sub-regulation shall be substituted, namely :-

‘(1) On and from the 2<sup>nd</sup> day of June, 2005, an officer shall be eligible for the following while traveling on duty, namely:-

- (i) an officer in Junior Management Grade is entitled to travel by 1<sup>st</sup> Class or AC 2-tier Sleeper by train. He may, however, travel by air (economy class) if so permitted by the Competent Authority, having regard to the exigencies of business or public interest.

- (ii) an officer in Middle Management Grade is entitled to travel by 1<sup>st</sup> Class or AC 2-tier Sleeper by train or he may travel by air (economy class) if the distance to be travelled is more than 1000 kms. or for a shorter distance if so permitted by the Competent Authority, having regard to the exigencies of business or public interest.
- (iii) an officer in Senior Management or Top Executive Grade is entitled to travel by AC 1<sup>st</sup> Class by train or by air (economy class).
- (iv) an officer in Senior Management or Top Executive Grade may travel by car between places not connected by air or rail provided that the distance does not exceed 500 km. and when a major part of the distance between the two places can be covered by air or rail only the rest of the distance should normally be covered by car.
- (v) any other officer may be authorised by the Competent Authority, having regard to the exigencies of business, to travel by his own vehicle or by taxi or by the Bank's vehicle.

(b) in sub-regulation (4), for clause (a), the following clause shall be substituted, namely:-

- (a) Halting Allowance - On and from the 1st day of June, 2005 an officer shall be entitled to per diem Halting Allowance as specified in the table below, namely:-

TABLE

Grades/Scales of officers	Major 'A' Class cities	Area I	Other Places
1	2		
Officers in Scale IV and above	Rs. 600	Rs. 550	Rs. 500
Officers in Scale I/II/III	550	500	400

Provided that in the case of officers in Scale IV and above, halting allowance payable per diem while on outstation work at the four metros, viz. Delhi, Mumbai, Kolkata and Chennai, shall be Rs.700;

Provided further that where the total period of absence is less than eight hours but more than four hours, Halting Allowance at half the above rates shall be payable.

Explanation : For the purpose of computing Halting allowance 'per diem' shall mean each period of twenty four hours or any subsequent part thereof, reckoned from the reporting time for departure in the case of air travel and the scheduled time of departure in other cases, to the actual time of arrival and where the total period of absence is less than twenty four hours 'per diem' shall mean a period of not less than eight hours.

11. In the said regulations, in regulation 42, for sub-regulation (3) the following sub-regulation shall be substituted, namely:-

'(3) On and from the first day of April, 1997 an officer on transfer shall be eligible to draw a lump sum amount for expenses connected with packing, local transportation, insuring the baggage, etc. as specified in the table below, namely,

TABLE

Grade	Lump Sum
Top Executive and Senior Management	Rs.5,000
Middle Management and Junior Management	Rs.4,000

Provided that on and from the first day of May, 2005 the provisions of this sub-regulation shall have effect as if for the letters and figures "Rs.5000" and "Rs.4000", the letters, words and figures "Rs.8750" and "Rs.7000" had been respectively substituted.'

12. In the said regulations, for regulation 44, the following regulation shall be substituted, namely:-



#### ‘44 Leave Travel Concession:

- (1) During each block of four years, an officer shall be eligible for leave travel concession for travel to his home town once in each block of two years, or; alternatively, he may travel in one block of two years to his home town and in another block of two years to any place in India by the shortest route.
- (2) An officer, by exercising an option at anytime during a block of four years or two years, as the case may be, may also surrender and encash his Leave Travel Concession (other than travel to home town) upon which he shall be entitled to receive an amount equivalent to 75% of the eligible fare for the class of travel by train to which he is entitled upto a distance of 4500 kms. (one way) for officers in JMG Scale I and MMG Scale II and III and 5500 kms (one way) for officers in SMG Scale IV and above and while opting to encash his Leave Travel Concession shall prefer the claim for himself or herself and his or her family members only once during the block or term in which such encashment is availed off and the facility of encashment of privilege leave while availing of Leave Travel Concession shall also be available while encashing the facility of Leave Travel Concession.
- (3) The mode and class by which an officer may avail of Leave Travel Concession shall be the same as the officer is normally entitled to travel on transfer and other terms and conditions subject to which the Leave Travel Concession may be availed of by an officer shall be as decided by the Board from time-to-time.
- (4) Once in every four years when an officer avails of Leave Travel Concession, he may be permitted to surrender and encash his Privilege Leave not exceeding thirty days at a time, or, he may whilst travelling in one block of two years to his home town and in other block to any place in India, be permitted encashment of Privilege Leave with a **maximum of fifteen days in each block or thirty days in one block and for the purpose of leave encashment all the emoluments payable for the month during which the Leave Travel Concession is availed, shall be admissible.**  
**Provided that an officer at his option shall be permitted to encash one day's additional privilege leave for donation to the Prime Minister's Relief Fund subject to his giving a letter to the Bank to that effect and authorizing the Bank to remit the amount to the Fund.'**

## Schedule to (Dena Bank (Officers') Service Regulations, 1979)

(See, sub-regulation ( 2) of regulation 23)

With effect from the 1st day of November, 2002, an officer shall be eligible for the Special Area Allowance till such time they are withdrawn or modified either wholly or partially, as specified in the table below, namely:-

TABLE

Serial number	Places where the allowance is payable	Rates of allowance payable	
		Pay from Rs.10,000 to Rs.14,000	Pay from Rs.14,001 and above
1.	Mizoram	(Rs.)	(Rs.)
	(a) Chimpitupui District of Mizoram and areas beyond 25 kms. from Lunglei Town in Lunglei District of Mizoram.	1,000	1,300
	(b) Throughout Lunglei District excluding areas beyond 25 kms. from Lunglei town of Mizoram.	800	1,050
	(c) Throughout Aizawl District of Mizoram	600	750
2.	Nagaland	800	1,050
3.	Andaman and Nicobar Islands		
	(a) South Andaman (including Port Blair)	800	1,050
	(b) North and Middle Andaman, Little Andaman, Nicobar and Narcondum Islands	1,000	1,300
4.	Sikkim	1,000	1,300
5.	Lakshadweep Islands	1,000	1,300
6.	Assam	160	200
7.	Meghalaya	160	200

Serial number	Places where the allowance is payable	Rates of allowance payable	
		Pay from Rs.10,000 to Rs.14,000	Pay from Rs.14,001 and above
8.	Tripura		
	(a) Difficult areas of Tripura	800	1,050
	(b) Throughout Tripura except difficult areas.	600	750
9.	Manipur	600	750
10	Arunachal Pradesh		
	(a) Difficult areas of Arunachal Pradesh	1,000	1,300
	(b) Throughout Arunachal Pradesh except difficult areas.	800	1,050
11.	Jammu and Kashmir		
	(1) Kathua District	1,000	1,300
	(a) Niabat Bani		
	(b) Lohi		
	(c) Malhar		
	(d) Macchodi		
	(2) (a) Udhampur District	1,000	1,300
	i. Dudu Basantgarh		
	ii. Lander Bhamag Illaqa		
	iii. Thakrakote		
	iv. Nagote		
	(b) All areas in Mohre Tehsil other than those included in 2(c).	1,000	1,300
	(c) Areas upto Goel from Kamban Side and areas upto Arnas from Keasi side in Tehsil Mohre.	800	1,050

Serial number	Places where the allowance is payable	Rates of allowance payable	
		Pay from Rs.10,000 to Rs.14,000	Pay from Rs.14,001 and above
	(3) Doda District  Illaqas of Padder and Niabat Nowgam in Kishtwar Tehsil	1,000	1,300
	(4) Leh District  All places in the District	1,000	1,300
	(5) Barmulla District  a) Entire Gurez-Nirabat, Tangdar Sub-Division and Keran Illaqa  b) Matchill	1,000  800	1,300  1,050
	(6) Poonch and Rajouri District :  Areas in Poonch and Rajouri District excluding the towns of Poonch and Rajouri and Sunderbani and other urban areas in the two Districts.	600	750
	(7) Areas not included in (1) to (6) above, but which are within the distance of 8 kms. from the line of Actual Control or at places which may be declared as qualifying for border allowance from time-to-time by the State Government for their own staff.	600	750
	Himachal Pradesh  (1) Chamba District  1(a) Pangi Tehsil  1(b) Following Panchayat and Villages of Bharmour Tehsil (i) Panchayats : Badgaun, Bajol, Deol Kugti, Nayagam and Tundah	1,000  800	1,300  1,050

Serial number	Places where the allowance is payable	Rates of allowance payable	
		Pay from Rs.10,000 to Rs.14,000	Pay from Rs.14,001 and above
	(ii) Villages: Ghatu of Gram Panchayat Jagat, Kanarsi of Gram Panchayat Chauhata		
	2. Bharmour Tehsil, excluding Panchayats and Villages included in Part 1.b above.	600	750
	3. Jhandru Panchayat in Bhatiyat Tehsil, Churah Tehsil, Dalhousie Town (including Banikhet proper).		
	(2) Kinnaur District:		
	(a) Asrang, Chitkul and HangoKuno/Charang Panchayats, 15/20 Area comprising the Gram Panchayats of Chhota Khamba, Nathpa and Ruppi, Pooh Sub-Division, excluding the Panchayat Areas specified above.	1,000	1,300
	(b) Entire District other than Areas included in (a) above	600	750
	(3) Kullu District:		
	3(a) 15/20 Area of Nirmand Tehsil, comprising the Gram Panchayats of Kharga, Kushwar and Sarga	1,000	1,300

Serial number	Places where the allowance is payable	Rates of allowance payable	
		Pay from Rs.10,000 to Rs.14,000	Pay from Rs.14,001 and above
	3(b) Outer-Seraj (excluding villages of Jakat-Khana and Burrow in Nirmand Tehsil) and entire District (excluding outer Seraj area and pargana of Pandrabis but including villages Jagat-Khana and Burrow of Tehsil Nirmand).	600	750
	(4) Lahaul and Spiti District : Entire area of Lahaul and Spiti.	1,000	1,300
	(5) Shimla District : (a) 15/20 area of Rampur Tehsil comprising of Panchayats of Koot, Labana-Sadana, Sarpara and Chadi-Branda.	1,000	1,300
	(b) Dodra-Kawar Tehsil, Gram Panchayat of Darkali in Rampur, Kashapath Tehsil and Munish, Ghor Chaibis of Pargana Sarahan.	800	1,050
	(c) Chopal Tehsil and Ghoris, Panjgaon, Patsnau, Naubis and Teen Koti of Pargana Sarahan, Deothi Gram Panchayat of Taklesh Area, Pargana Barabis, Kasba Rampur and Ghor Nog of Pargana Rampur of Rampur Tehsil, Shimla Town and its suburbs (Dhalli, Jatog, Kasumpti, Mashobra, Taradevi and Tutu).	600	750

Serial number	Places where the allowance is payable	Rates of allowance payable	
		Pay from Rs.10,000 to Rs.14,000	Pay from Rs.14,001 and above
	(6) Kangra District:		
	(a) Areas of Bara Bhangal and Chhota Bhangal	800	1,050
	(b) Dharamshala Town of Kangra District and the following offices located outside the Municipal limits but included in Dharamshala Town— Women's ITI, Dari, Mechanical Workshop, Ramnagar, Child Welfare and Town and Country Planning Offices, Sakoh, CRSF Office at lower Sakoh, Kangra Milk Supply Scheme, Dugiari, HRTC Workshop, Sadher, Zonal Malaria Office, Dari, Forest Corporation Office, Shamnagar, Tea Factory, Dari, I.P.H. Sub-Division, Dan, Settlement Office, Shamnagar, Binwa Project, Shamnagar Office/Jersey Farm, Banuri, Sericulture Office/Indo-German Agriculture Workshop/HPPWD Division, Bundla, Electrical Sub-Division, Lohna, D.P.O. Corporation, Bundla, Electrical HPSEE Division, Ghuggar.	600	750
	(7) Mandi District:		
	Chhuahar Valley of Jogindernagar Tehsil, Panchayats in thunag	600	750

Serial number	Places where the allowance is payable	Rates of allowance payable	
		Pay from Rs.10,000 to Rs.14,000	Pay from Rs.14,001 and above
	<p>Tehsil-of Bagraa, Chatri, Chhotdhar, Garagushain, Gato, Garyas, Janjehli, Jaryar, Johar, Kalhani, Kalwan, Kholanal, Loth, Silibagi, Somachan, Thachdhar, Tachi, Thana, Panchayats of Dharampur Block- Binga, Kamlah, Saklana, Tanyar and Tarakholah, Panchayats of Karsog Tehsil – Balidhar, Bagra, Gopalpur, Khajol, Mahog, Mehudi, Manj, Pekhi, Sainj, Sarahan and Teban, Panchayats of Sundernagar Tehsil – Bohi, Batwara, Dhanyara, Paura-Kothi, Seri and Shoja.</p> <p>(8) Sirmaur District:</p> <p>(a) Panchayats of Bani, Bakhali (Pachhad Tehsil), Bharog Bheneri (Paonta Tehsil), Birla (Nahan Tehsil), Dibber (Pachhad Tehsil) and Thana Kasoga (Nahan Tehsil).</p> <p>(b) Thansgiri Tract</p>		
	<p>(9) Solan District :</p> <p>Mangal Panchayat.</p>	600	750
	<p>(10) Remaining areas of Himachal Pradesh not included in (1) to (9) above.</p>	160	200



Serial number	Places where the allowance is payable	Rates of allowance payable	
		Pay from Rs.10,000 to Rs.14,000	Pay from Rs.14,001 and above
13.	Uttar Pradesh: Areas under Chamoli, Pithoragarh and Uttar Kashi Districts:  2(a) Other area of District Pithoragarh and Uttarkashi (including District Headquarters of Uttarkashi).  2(b) Champawat District (including area of Lohaghat).	1,000	1,300
14.	Uttaranchal:  Areas under Rudraprayag and Champavat Districts.	800	1,050

R. SRIDHARAN, General Manager (HRM)

[ADVT. III/4/130/11-Exty.]

Note : The principal regulations were published in the Official Gazette on the 1-7-1979.